CNews सिटी चीफ

सिटी चीफ

वर्ष-15, अंक-315
पृष्ठ-8 मूल्य 2 रूपया

सच्चाई एक ऐसा दीपक है, जिसके प्रकाश से ही संसार प्रकाशित रहता है।

CITYCHIEFSENDMENEWS@GMAIL.COM

इंदौर, बुधवार 19 फरवरी 2025

सम्पूर्ण भारत मे चर्चित हिन्दी अखबार

इंदौर और भीकनगांव में आयकर विभाग के छापे

मीडिया हाउस के मालिक और रियल इस्टेट कारोबारी आईटी के निशाने पर

आयकर विभाग की टीम ने मंगलवार सुबह इंदौर और खरगोन के समीप भीकनगांव में रियल एस्टेट कारोबारी के यहां छापे मारे। इंदौर के बालाजी विहार, महू नाका स्थित मीडिया हाउस के मालिक और रियल इस्टेट कारोबारी हृदयेश दीक्षित के यहां सुबह टीम पहुंची। जब परिवार के लोग सोए हुए थे। दीक्षित परिवार के यहां सोमवार को पार्टी थी। इस कारण परिवार के लोग देर रात को ही घर लौटे थे और मंगलवार सुबह आयकर की टीम ने दस्तक दे दी। बताया जा रहा है कि 17 फरवरी सोमवार को हृदेश दीक्षित की मैरिज एनिवर्सरी थी. रात 2 बजे तक वे एनिवर्सरी पार्टी में थे. इसके बाद घर लौटे और कुछ समय बाद इनकम टैक्स की टीम पहुंच गई। हृदेश दीक्षित रियल एस्टेट से भी जुड़े हैं। उनके परिवार की ग्लोबल ट्रेड वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड नामक बड़ी कंपनी है। इसे लेकर भी छानबीन चल रही है। टीम ने बीते सालों में उनके ठिकानों पर चौथी बार छापा मारा है. करीब 10 साल पहले भी हृदेश दीक्षित पर आयकर छापा पड़ा था, जिसमें एंट्री के लेन-देन और बोगस बिलिंग का मामला सामने आया था। अफसरों ने सबसे पहले परिवार के सदस्यों के फोन लिए और जांच होने तक किसी को भी घर से बाहर निकलने की इजाजत नहीं दी। मीडिया हाउस के मालिक होने के अलावा हृदयेश रियल एस्टेट कारोबार से भी जुड़े हैं। परिवार के साथ ग्लोबल ट्रेड वेंचर्स कंपनी से भी जुड़े हैं। छापा इस कंपनी की जांच के लिए ही मारा गया है। दीक्षित परिवार के यहां वर्ष 2009 में भी आयकर विभाग की टीम ने छापा मारा था। तब महिला व बाल विकास विभाग के पोषण आहार के ठेके और उससे जुड़ी दो फैक्टरियों के बारे में पता चला था। इसके अलावा भीकनगांव में अनंत एग्रो एजेंसी पर भी आयकर विभाग ने जांच की। एजेंसी का कॉटन के अलावा जमीनों की खरीदी बिक्री का कारोबार है। अफसरों ने रिकार्ड खंगाले। यहां टीम सुबह चार बजे पहुंची थी। वहीं खरगोन के भीकनगांव में आयकर की टीम सुबह 4.30 बजे झिरन्या रोड स्थित अनंत एग्रो इंडस्ट्रीज में पहुंची। अनंत एग्रो एजेंसी का भीकनगांव के अलावा खंडवा और इंदौर में भी फर्म के नाम से कारोबार है। उनका ऑर्गेनिक कॉटन के अलावा जमीनों की खरीदी बिक्री का कारोबार है। यहां दस्तावेजों की जांच पड़ताल की गई। करीब 12 से अधिक अधिकारी-कर्मचारी दस्तावेज खंगालने में लगे रहे।

यूनियन कार्बाइड कचरे के निपटान के टेस्ट की मप्र हाईकोर्ट ने दी मंजूरी

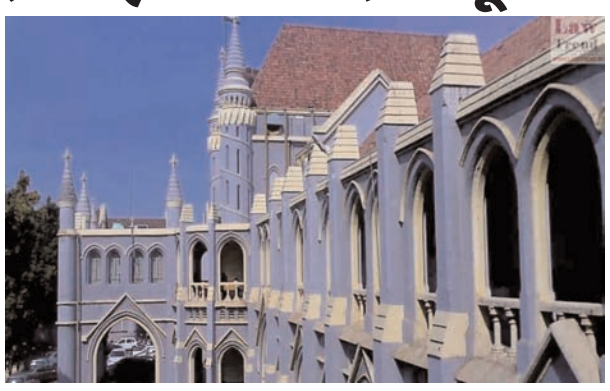

जबलपुर। मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय ने प्रदेश सरकार को भोपाल स्थित बंद पड़े यूनियन कार्बाइड कारखाने से निकले 40 वर्ष पुराने रासायनिक कचरे को धार जिले के पीथमपुर क्षेत्र में निस्तारण का परीक्षण करने की मंगलवार को अनुमति दे दी। महाधिवक्ता प्रशांत सिंह ने यहां सुनवाई के बाद मीडिया को बताया कि 27 फरवरी से तीन चरणों में परीक्षण के तौर पर कचरे का निस्तारण किया जाएगा।उन्होंने बताया कि सरकार ने मंगलवार को कचरा निस्तारण प्रक्रिया के बारे में जन जागरूकता फैलाने के लिए उठाए गए कदमों के बारे में जनवरी में उच्च न्यायालय द्वारा मांगी गई अनुपालन रिपोर्ट दाखिल की। पीथमपुर के स्थानीय लोग अपने क्षेत्र में कचरे के नियोजित निस्तारण का कड़ा विरोध कर रहे हैं। आपको बताते चलें कि 1984 में घटी भोपाल गैस त्रासदी में 5000 से अधिक लोगों की मौत हो गयी थी। सरकार ने अदालत से अनुरोध किया था कि जागरूकता अभियान चलाया गया है और अब निस्तारण का परीक्षण करने की अनुमति दी जानी चाहिए। सिंह ने बताया कि परीक्षण तीन चरणों में किया जाएगा, जिसमें प्रत्येक चरण में 10 टन कचरे का निस्तारण होगा। उन्होंने बताया कि पहले परीक्षण में 135 किलोग्राम प्रति घंटे की दर से कचरे का निस्तारण किया जाएगा जबकि दूसरे और तीसरे चरण में इसे बढ़ाकर 180 किलोग्राम प्रति घंटे और 270 किलोग्राम प्रति घंटे किया जाएगा। महाधिवक्ता ने बताया कि उच्च न्यायालय के निदेर्शों के अनुसार, पहला परीक्षण 27 फरवरी को और दूसरा चार मार्च को किया जाएगा हालांकि तीसरे परीक्षण की तारीख अब तक तय नहीं की गई है। यूनियन कार्बाइड संयंत्र से कुल 337 टन खतरनाक कचरा पीथमपुर निस्तारण संयंत्र पहुंचाया गया है। अदालत में 27 मार्च को अनुपालन रिपोर्ट पेश की जाएगी।

मोहन सरकार में फिर से नीतियों की बौछार- ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट-2025 से पहले मप्र की कैबिनेट बैठक में 7 नई नीतियों को मिली मंजूरी

मॉडल इलेक्ट्रिक सिटी बनेंगे इंदौर,भोपाल, उज्जैन, ग्वालियर और जबलपुर

भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को कैबिनेट की बैठक हुई। इस बैठक में कैबिनेट के सभी मंत्री शामिल हुए। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट-2025 के पहले सरकार ने कैबिनेट बैठक में प्रदेश के विकास से जुड़े कई अहम फैसले लिए हैं। मोहन सरकार ने 7 नई नीतियों को मंजूरी दी। इन नई नीतियां से व्यापार और निवेश आसानी होगी। सरकार ने नई एमएसएमई और नई स्टार्टअप नीति को मंजूरी दी, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए भी नई नीति बनाई गई। वहीं एकीकृत टाउनशिप के लिए नए नियम बनाए गए । इसके अलावा मध्यप्रदेश नागरिक विमानन नीति को भी कैबिनेट ने हरी झंडी दी है। इलेक्ट्रिक वाहन नीति के तहत मध्यप्रदेश में भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर और उज्जैन को मॉडल इलेक्ट्रिक सिटी के रूप में विकसित किया जाएगा। यहां ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रिक वाहनों के चलाने पर जोर दिया जाएगा। इसके लिए ई-व्हीकल में रजिस्ट्रेशन में 15 से लेकर 80 फीसदी तक की छूट दी जाएगी। ई-व्हीकल के रजिस्ट्रेशन में दो पहिया वाहन में 40, कॉमर्शियल 100, तिपहिया वाहन के लिए 80, चार पहिया के लिए 15 प्रतिशत और इलेक्ट्रिक बस के लिए 40 फीसदी छूट दी जाएगी। वाहनों के चार्जिंग स्टेशन बनाने सब्सिडी दी जाएगी। पेट्रोल पम्प पर ही चार्जिंग स्टेशन बनाने की अनुमति दी जाएगी। दो साल के भीतर प्रदेश के सभी सरकारी वाहन को ईवी में कन्वर्ट किया जाएगा। इस अ ?वधि में 80 फीसदी वाहन ईवी में बदले जाएंगे।

चार्जिंग स्टेशन महिलाओं, दिव्यांगों द्वारा लगाए जाने पर सहायता दी जाएगी। कम से कम 20 किमी पर एक चार्जिंग स्टेशन होगे। राजमार्ग पर हर 100 किमी दूरी पर कम से कम एक फास्ट चार्जिंग स्टेशन हो। पांच साल तक के लिए यह पालिसी लागू रहेगी। एक किमी पर एक चार्जिंग स्टेशन भी होंगे। चार्जिंग अधोसंरचना के लिए शासन अलग से सहायता देगा।

मप्र की नई एमएसएमई नीति को मंजूरी मप्र की नई एमएसएमई नीति से प्रदेश में 86 लाख रोजगार का सृजन होगा। सरकार ईज ऑफ डुइंग को प्रोत्साहित करेगी। 53 हजार करोड़ के निवेश का लक्ष्य रखा गया है। नवीन उद्योगों में नवकरणीय ऊर्जा को प्रोत्साहन दिया जाएगा। मशीनरी-बिल्डिंग में निवेश पर 40 फीसदी सब्सिडी दी जाएगी। मशीनरी में 10 करोड़ तक निवेश पर महिलाओं को सब्सिडी दी जाएगी। अजा/अजजा/महिला उद्यमी को 48 और 52 फीसदी सब्सिडी मिलेगी। 10 करोड़ से अधिक का उद्योग लगाने पर अनुदान मिलेगा। निवेशकों को 1.5 गुना अतिरिक्त अनुदान मिलेगा टेक्सटाइल में निवेश करने वालों को विशेष पैकेज मिलेगा। निर्यात को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार की पहल होगी कि माल ढुलाई में 40 लाख तक की प्रतिवर्ष सहायता दी जाएगी।

5 वर्षों तक माल ढुलाई में मिलेगी आर्थिक सहायता। निर्यात संबंधी प्रमाण पत्र के लिए 50 लाख तक की मदद मिलेगी। एमएसएमी नीति में रोजगार सृजन पर मिलेगा अनुदान। 10 करोड़ से अधिक के उद्योगों पर मिलेगा अनुदान। 100 से अधिक रोजगार देने पर 1.5 गुना अतिरिक्त अनुदान मिलेगा। रिसाइक्लिंग इकाई के लिए 2 करोड़ तक की मदद मिलेगी।

कैबिनेट में स्टार्ट अप नीति को भी मंजूरी दी गई है। मेगा इन्क्यूबेशन सेंटर खोले जाएंगे। अभी 5 हजार स्टार्ट अप हैं। इसे आने वाले समय में दस हजार स्टार्ट अप तक ले जाने का काम किया जाएगा। इसके लिए इन्क्यूबेशन सेंटर की स्थापना की जाएगी। प्राप्त निवेश पर ऋण सहायता दी जाएगी। बाजार तक पहुंच, ऋण सहायता, हैक थान, रोजगार सृजन सहायता, कौशल सहायता, संस्थागत सहायता, नवाचार और प्रोत्साहन योजना, अधोसंरचना सहयोग, लीज रेंट में सहायता कर ऋण देने का काम किया जाएगा। स्टार्ट अप सलाहकार परिषद की स्थापना की जाएगी।

अविकसित भूमि आवंटन नीति एमएसएमई को बढ़ावा देने के लिए अविकसित भूमि आवंटन नीति भी मंजूर की गई है। पात्र, मध्यम और विशेष परिस्थिति में यह आवंटन किया जाएगा। औद्योगिक क्षेत्र का संधारण उद्योग संगठन करना चाहेंगे तो सरकार उन्हें इसे देगी और आवश्यक मार्गदर्शन और सहायता सरकार देगी। परियोजना में 50 फीसदी स्थायी पूंजी निवेश पर ही यह सुविधा दी जाएगी। भूमि की अनुपलब्धता पर फ्लैट भी दिए जाने का काम किया जाएगा। आनलाइन आवेदन मिलने के बाद पात्र आवेदक को भूमि का आवंटन किया जाएगा। एक से अधिक आवेदन पर ई बिडिंग से आवंटन किया जाएगा। प्रक्रिया पारदर्शी बनाने पर जोर दिया गया है।

मप्र की इंटीग्रेटेड टाउनशिप नीति 2025 अभी तक टाउनशिप काटने का काम बिल्डर, कॉलोनाइजर करते हैं। मप्र की इंटीग्रेटेड टाउनशिप नीति 2025 में समूह यह काम कर सकता है। किसान अगर मिलकर एक एकड़ में टाउनशिप बनाना चाहते हैं तो सरकार इसमें सहयोग करेगी। इसके जरिए इन्वेस्टमेंट लाने और नियोजित विकास को बढ़ावा देंगे। किफायती आवास बनाने वालों को अलग से सब्सिडी देंगे। लैंड पुलिंग के माध्यम से सार्वजनिक और निजी भागीदारी को प्रोत्साहित करेंगे। जिला और राज्य स्तर पर साधिकार समिति बनाकर प्रोजेक्ट को मंजूरी देंगे। आवेदन देने के बाद साठ दिन के भीतर परमिशन मिलेगी।

नई विमानन नीति- हर 150 किमी पर एक एयरपोर्ट मप्र की नई विमानन नीति के तहत हर 150 किमी पर एक एयरपोर्ट विकसित किया जाएगा। पर्यटन को आकर्षित करने और धार्मिक पर्यटन को बढ़ाने के लिए नगर विमानन नीति बनाई गई है। हर 150 किमी पर एक एयरपोर्ट विकसित किया जाएगा। 45 किमी दूरी पर एक हेलीपैड भी बनाया जाएगा। धार्मिक और पर्यटन स्थलों को इससे जोड़ने के साथ रोजगार भी मिलेगा। पायलट प्रशिक्षण, एयर कार्गो की सुविधा बढ़ेगी। फूड, फिश और अन्य सामग्री एयर कार्गो के जरिए दूसरे स्थान पर भेजी जा सकेगी।

नवीकरणीय ऊर्जा में बायो फ्यूल को जोड़ेंगे प्रदेश के बाहर बिजली बेचने पर 10 प्रतिशत हरित ऊर्जा टैक्स लगता था। इस ऊर्जा टैक्स को खत्म करने का फैसला किया गया है। विद्युत परियोजनाओं को बायो फ्यूल से जोड़ने पर भी विचार किया जा रहा है। नवीकरणीय ऊर्जा में बायो फ्यूल को जोड़ने का काम किया जाएगा। सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, विंड-सौर, हाइब्रिड ऊर्जा, सोलर-थर्मल परियोजना के लिए 1000 मेगावाट संयंत्र के लिए 24 माह और इससे अधिक मेगावाट की परियोजना के लिए 30 माह का समय देगी। बायो फ्यूल यूनिट के लिए पांच करोड़ तक की सहायता दी जाएगी। 500 करोड़ से अधिक के निवेश पर अनुकूल पैकेज देंगे।

गेस्ट टीचर्स की पीएचडी अनिवार्यता पर मप्र हाईकोर्ट ने लगाई रोक

जबलपुर। मध्यप्रदेश के सरकारी कॉलेजों के गेस्ट टीचर्स को मंगलवार को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। मामले पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने अतिथि शिक्षकों के लिए पीएचडी की अनिवार्यता पर रोक लगा दी है। हाईकोर्ट ने अतिथि शिक्षक भर्ती नियम की धारा 10.4 पर भी रोक लगा दी है। हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान यह भी कहा कि पुरानी भर्तियों पर नए नियम लागू नहीं हो सकते हैं। राज्य सरकार ने असिस्टेंट प्रोफेसर्स के लिए जारी नियम अतिथि शिक्षकों पर भी लागू कर दिए थे, जिसे हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी। हाईकोर्ट में यह याचिका अतिथि शिक्षक प्रियंका उपाध्याय, पुष्पा चतुर्वेदी सहित अन्य 13 लोगों ने दायर की थी। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस सुरेश कुमार कैथ और जस्टिस विवेक जैन की डिवीजन बेंच ने मामले में सुनवाई की। मध्यप्रदेश शासन ने 23 अक्टूबर 2023 को अतिथि विद्वानों की नियुक्ति को लेकर नए दिशा-निर्देश कंडिका (पैराग्राफ) 10.6 के तहत जारी कर दिए थे। इसे आधार बनाते हुए याचिकाकर्ताओं ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। याचिकाकर्ताओं का कहना था कि एक तरफ तो जो अतिथि विद्वान पहले से कार्यरत हैं, उन्हें यथावत रखा जाएगा, लेकिन फेलन आउट (जिनका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो चुका है) अतिथि विद्वानों को बगैर पीएचडी के कंटीन्यू नहीं किया जाएगा।

ईडब्लूएस को छूट का यूपीएससी ने किया तगड़ा विरोध...लेकिन हाईकोर्ट ने नहीं सुनी बात

मप्र उच्च न्यायालय अपने आदेश पर अडिग, ईडब्लूएस को पांच वर्ष की आयु सीमा की छूट बरकार रखी

जबलपुर। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी ईडब्लूएस को आरक्षित वर्ग जैसी छूट का संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) ने तगड़ा विरोध किया। जबलपुर में हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सुरेश कुमार कैत और न्यायमूर्ति विवेक जैन की युगलपीठ ने सोमवार को ईडब्ल्यूएस वर्ग के उम्मीदवारों को आयुसीमा में 5 वर्ष की छूट दी थी। इसके बाद मंगलवार को हुई सुनवाई में इसका यूपीएससी ने विरोध किया। हालांकि कोर्ट ने यूपीएससी का विरोध फिलहाल दरकिनार कर दिया है। अपने पूर्व आदेश पर अडिग रहते हुए हाईकोर्ट ने ईडब्लूएस को पांच वर्ष की आयु सीमा की छूट और 9 अटेम्प्ट का फैसला बरकार रखा है। इस मामले में अंतिम सुनवाई 24 फरवरी को रखी गई है। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने ईडब्ल्यूएस वर्ग को 5 साल की आयु सीमा की छूट देने का आदेश बरकरार रखते हुए यूपीएससी को इसका पालन करने को कहा है। कोर्ट ने कहा कि अंतरिम आदेश में स्पष्ट है कि ईडब्ल्यूएस को आयु सीमा की यह छूट विचाराधीन याचिका के अंतिम निर्णय के अधीन होगी। हाईकोर्ट ने यूपीएससी को अंतरिम आदेश का पालन करने का निर्देश दिया।

यूपीएससी ने कहा- दिक्कत आएगी मंगलवार को सुनवाई में यूपीएससी की ओर हाईकोर्ट के निर्णय का विरोध किया गया। दलील दी गई कि अंतिम समय में आयुसीमा छूट संबंधी अंतरिम आदेश से यूपीएससी को सिविल सेवा परीक्षा 2025 के संचालन में दिक्कत आएगी। बता दें कि मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने सोमवार को बड़ा फैसला सुनाते हुए ईडब्लूएस को कई छूटें दीं। कोर्ट ने सिविल सेवा परीक्षा (यूपीएससी) 2025 के लिए ये राहत दी हैं। आयुसीमा में आरक्षित वर्ग जैसी छूट दी गई है। हाईकोर्ट ने न केवल हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद ईडब्लूएस के ऐसे अनेक उम्मीदवार भी आवेदन कर सकेंगे जो आयुसीमा या अटेम्प्ट के मौके खत्म होने के कारण इससे वंचित हो गए थे। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यह अंतरिम राहत याचिका के अंतिम निर्णय के अधीन होगी।

डंपर ने लोडिंग वाहन को टक्कर मारी, 6 की मौत, सभी आपस में रिश्तेदार

भिंड। भिंड के जवाहरपुरा गांव के पास तेज रफ्तार डंपर ने सड़क किनारे खड़े लोडिंग वाहन को टक्कर मार दी। हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई। 19 घायल हैं। लोडिंग वाहन को टक्कर मारने के बाद डंपर ने बाइक को भी चपेट में ले लिया। एक्सीडेंट नेशनल हाईवे क्रमांक 719 पर मंगलवार सुबह करीब 5 बजे हुआ। हादसे के शिकार सभी लोग जवाहरपुरा गांव में शादी से अपने गांव भवानीपुरा लौट रहे थे। सभी आपस में रिश्तेदार हैं। डंपर ड्राइवर मौके से भाग निकला। हादसे के बाद ग्रामीणों ने जाम लगा दिया। हाईवे को सिक्सलेन बनाने की मांग करते हुए कलेक्टर, एसपी और सांसद समेत अन्य जनप्रतिनिधियों के खिलाफ नारेबाजी की। मौके पर मौजूद पुलिस अधिकारियों ने उन्हें समझाने की कोशिश की लेकिन वे नहीं माने। जानकारी लगते ही कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव, एसपी असित यादव, एसडीएम अखिलेश शर्मा, डीएसपी दीपक तोमर वहां पहुंचे और लोगों से बातचीत की। उनकी मांग ऊपर पहुंचाने का भरोसा दिलाया। करीब 4 घंटे बाद जाम खुल सका। इस दौरान व्यवस्था संभालने के लिए चार थानों का पुलिस बल बुलाया गया था।

दुनिया की शीर्ष आठ क्रिकेट टीमों के बीच आज से होगी चैंपियंस ट्रॉफी की शुरुआत

नई दिल्ली। दुनिया की शीर्ष आठ टीमों के बीच बुधवार से चैंपियंस ट्रॉफी की शुरुआत होने जा रही है। आठ साल बाद इस टूर्नामेंट का आयोजन हो रहा है। दिलचस्प बात यह है कि इसका आयोजन हाइब्रिड मॉडल की तर्ज पर होगा जिसमें इसके मुकाबले पाकिस्तान और दुबई में खेले जाएंगे। भारत ने चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान की यात्रा करने से इनकार कर दिया था जो टूर्नामेंट का मेजबान है जिसके बाद आईसीसी ने भारत के मुकाबले दुबई में कराने का फैसला किया था। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए आठ टीमों को दो ग्रुप में बांटा गया है। ग्रुप ए में भारत, पाकिस्तान, न्यूजीलैंड और बांग्लादेश हैं, जबकि ग्रुप बी में दक्षिण अफ्रीका, अफगानिस्तान, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया हैं। अपने-अपने ग्रुप में शीर्ष दो टीमें सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करेंगी और दो टीमों के बीच नौ मार्च को फाइनल मुकाबला खेला जाएगा। भारत अगर टूर्नामेंट के खिताबी मुकाबले में पहुंचने में सफल रहा तो फाइनल मैच दुबई में ही आयोजित होगा। भारत के फाइनल में नहीं पहुंचने की स्थिति में यह लाहौर में खेला जाएगा।

कंडे से अंतिम संस्कार करने पर बवाल, गौभक्त और निगमकर्मी हुए आमने-सामने

सिटी चीफ इंदौर।

इंदौर। इंदौर के खजराना मुक्तिधाम में एक गौभक्तके अंतिम संस्कार को लेकर तब विवाद खड़ा हो गया, जब नगर निगम के कर्मचारियों ने गाय के कंडे से दाह संस्कार करने से इनकार कर दिया। इसको लेकर मुक्तिधाम पर काफी हंगामा हुआ और विवाद बढ़ता चला गया। लगभग 2 घंटे तक इस मुद्दे पर बहस होती रही और अंततः क्षेत्रीय पार्षद के हस्तक्षेप के बाद ही अंतिम संस्कार संभव हो पाया। इंदौर नगर निगम शहर के सभी श्मशान घाटों का संचालन करता है, जहां अंतिम संस्कार लकड़ी या कंडे के माध्यम से किया जाता है। नगर निगम द्वारा श्मशान घाटों पर लकड़ी और कंडे उपलब्ध कराने के लिए ठेका दिया गया है, जिससे अंतिम क्रिया के लिए आवश्यक सामग्री वहीं से प्राप्त होती है। खजराना श्मशान घाट पर उस समय विवाद की स्थिति बन गई, जब बंगाली चौराहे के पास स्थित चेतन नगर निवासी गौभक्त विष्णु शर्मा का अंतिम संस्कार

करने के लिए उनके साथी पहुंचे। शर्मा लंबे समय से गौसेवा में सक्रिय थे और उन्होंने शहर में लगभग 30 गौशालाओं के संचालन में सहयोग दिया था। उनके निधन के बाद उनके गौभक्त मित्रों ने फैसला किया कि उनका दाह संस्कार गाय के कंडे से ही किया जाएगा।

लोग खुद कंडे लाए तो कर्मचारी नाराज हुए

इसके लिए पहले से ही कुछ गौसेवक मुक्तिधाम पर पहुंच गए और अपने साथ गाय के कंडे भी लेकर आए। लेकिन जब मुक्तिधाम के कर्मचारियों ने इसे देखा, तो उन्होंने इस पर आपत्ति जताई। उनका कहना था कि मुक्तिधाम में गाय के कंडे से अंतिम संस्कार करने की अनुमति नहीं दी जा सकती, और यदि कंडे से दाह संस्कार करना है, तो इन्हें नगर निगम द्वारा अधिकृत ठेकेदार से ही खरीदना होगा। इस बात से गौभक्त नाराज हो गए और उन्होंने नगर निगम के महापौर पुष्यमित्र भार्गव, क्षेत्रीय विधायक महेंद्र हार्डिया और निगम आयुक्त शिवम वर्मा से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन किसी ने भी कॉल नहीं उठाया। इस दौरान मृतक की शवयात्रा श्मशान घाट पहुंच चुकी थी, लेकिन अंतिम संस्कार की अनुमति को लेकर असमंजस बना रहा।

पार्षद ने समझाइश दी

इसी बीच क्षेत्रीय पार्षद प्रणव मंडल मौके पर पहुंचे। इससे पहले उन्होंने फोन के जरिए भी कर्मचारियों से समझाइश देने की कोशिश की थी, लेकिन कोई हल नहीं निकला था। जब वे वहां पहुंचे, तो उन्होंने नगर निगम के कर्मचारियों से बातचीत की और स्थिति को संभालने की कोशिश की। करीब 2 घंटे तक चले विवाद के बाद आखिरकार कर्मचारियों ने अनुमति दी और विष्णु शर्मा का अंतिम संस्कार गाय के कंडों से किया गया। यह घटना नगर निगम की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर रही है। जहां एक ओर धार्मिक रीति-रिवाजों का पालन करने की मांग की जा रही थी, वहीं दूसरी ओर प्रशासन की नीतियां आड़े आ रही थीं। हालांकि, इस मामले को लेकर नगर निगम की कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है, लेकिन इस विवाद के बाद शहर में अंतिम संस्कार के नियमों और व्यवस्थाओं को लेकर नई बहस छिड़ गई है।

आउटर रिंग रोड के विरोध में किसानों ने किया उग्र प्रदर्शन

सिटी चीफ इंदौर।

इंदौर। इंदौर में बनने वाली आउटर रिंग रोड और अहिल्या पथ जैसी बड़ी परियोजनाओं के लिए किसानों की जमीन का अधिग्रहण किया जाना है। इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए नेशनल हाईवे अथॉरिटी की टीम सर्वे करने विभिन्न गांवों में पहुंच रही है, लेकिन ग्रामीणों के विरोध के कारण सर्वे का कार्य शुरू ही नहीं हो पा रहा है। जब सोमवार कोअधिकारी ललेदीपुरा, मोहना और नाहरखेड़ा गांव पहुंचे, तो वहां पहले से ही विरोध के लिए किसान और ग्रामीण एकत्रित थे। लगभग दो घंटे तक ग्रामीणों ने जमकर हंगामा किया, जिसके बाद सर्वे टीम को बिना कोई काम किए वापस लौटना पड़ा। मंगलवार को भी किसानों का जगह जह प्रदर्शन चलता रहा और सर्वे का काम रुका रहा। इससे पहले भी मोहना गांव में अधिकारी सर्वे के लिए गए थे, लेकिन विरोध के कारण वे वहां से लौटने को मजबूर हो गए थे। इस बार जिला प्रशासन और पुलिस बल के साथ टीम पहुंची थी, लेकिन किसानों की नाराजगी के आगे वे भी कुछ नहीं कर सके। ग्रामीणों का कहना है कि बिना उनकी सहमति के भूमि अधिग्रहण नहीं होने दिया जाएगा।

सोशल मीडिया बना किसानों का हथियार

आउटर रिंग रोड से प्रभावित होने वाले गांवों के किसानों ने सोशल मीडिया पर अपना एक ग्रुप बना लिया है, जिसमें वे लगातार जानकारी साझा कर रहे हैं।

जैसे ही किसी गांव में सर्वे टीम पहुंचती है, तुरंत अन्य गांवों के किसानों को सूचित कर दिया जाता है, जिससे आस-पास के ग्रामीण भी विरोध करने के लिए वहां पहुंच जाते हैं। इस एकजुटता के कारण सर्वे टीम हर बार असहाय महसूस कर

रही है और अब तक सर्वे का कार्य सुचारू रूप से नहीं हो पाया है।

भारतीय किसान संघ ने किया विरोध तेज, 27 को धरना

भूमि अधिग्रहण के खिलाफ किसानों के आंदोलन को अब भारतीय किसान संघ का भी समर्थन मिल रहा है। संघ ने 27 फरवरी को कलेक्टर कार्यालय पर धरना देने की घोषणा की है, जिसमें आउटर रिंग रोड से प्रभावित सभी गांवों के किसान शामिल होंगे। किसानों का आरोप है कि नाममात्र की कीमत देकर उनकी उपजाऊ जमीन छीनी जा रही है, जिससे उनका जीवनयापन प्रभावित होगा। सोमवार को भारतीय किसान संघ ने मालवा प्रांत की 112 तहसीलों में ज्ञापन सौंपा, जिसमें सरकार से मांग की गई है कि भूमि अधिग्रहण से पहले जमीन की कीमत बढ़ाई जाए और किसानों को बाजार मूल्य से चार गुना अधिक मुआवजा दिया जाए। जब तक उचित मुआवजा तय नहीं किया जाता, तब तक किसी भी तरह का भूमि अधिग्रहण स्वीकार नहीं किया जाएगा।

किसानों का संकल्प- जमीन नहीं देंगे

किसानों ने साफ कर दिया है कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होतीं, वे किसी भी हालत में अपनी जमीन सरकार को नहीं देंगे। विरोध बढ़ता देख अब प्रशासन के लिए यह चुनौती बन चुका है कि विकास परियोजनाओं को आगे कैसे बढ़ाया जाए। किसानों के तीव्र विरोध के चलते आउटर रिंग रोड और अन्य योजनाओं के कार्यों में देरी होने की संभावना बढ़ गई है।

दीक्षित परिवार में हुए विवाह समारोह में पहुंचे राजस्थान के गवर्नर

सिटी चीफ इंदौर।

इंदौर। राजस्थान के गवर्नर हरीभाऊ बागडे मध्यप्रदेश में अपनी पहली निजी यात्रा पर प्रिया व विजय दीक्षित के छोटे बेटे तेजन दीक्षित एवं काजल के विवाह समारोह में पधारे। राजस्थान के गवर्नर ने नवयुगल को आशिर्वाद के साथ भेंट दी। दीक्षित परिवार के इस मांगलिक कार्यक्रम में गवर्नर के अलावा बॉलीवुड के प्रसिद्ध फिल्म अभिनेता पद्मश्री मनोज जोशी व भजन सम्राट पद्मश्री अनूप जलोटा, केंद्रीय ऊर्जा राज्य मंत्री श्रीपद नायक, केंद्रीय महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर, मध्यप्रदेश के स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा राज्य मंत्री नरेंद्र पटेल, कैबिनेट जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट, सांसद शंकर लालवानी, पूर्व मंत्री गिरिराज दंडोतिया, सहित अनेकों गणमान्य नागरिक शामिल हुए एवं शुभकामनाएं प्रेषित की। परिवार की और से बिटिया धनिष्का, डॉ. चेतना दीक्षित व एडवोकेट तनुज दीक्षित ने सभी अतिथियों का आभार माना।

पशु पकड़ने गई नगर निगम की टीम से विवाद के मामले में एफआईआर दर्ज

सिटी चीफ इंदौर।

इंदौर। पशु पकड़ने गई इंदौर नगर निगम की टीम से विवाद के मामले में एफआईआर दर्ज कराई गई है। मंगलवार को टीम भागीरथपुरा में सीएम हेल्पलाइन की शिकायत पर पशु पकड़ने पहुंची थी। यहां पर कार्रवाई के दौरान पशु पालकों ने झूमाझटकी की। एमजी रोड थाने में नगर निगम के कोंदवाड़ा विभाग में पदस्थ सुपरवाइजर राजेश शर्मा ने पशुपालक नानू यादव और उसके साथियों के खिलाफ केस दर्ज कराया है। सुबह राजेश शर्मा अपनी टीम के साथ सीएम हेल्पलाइन की शिकायत पर कार्रवाई करने भागीरथपुरा पहुंचे थे। जब पशु पकड़कर गाड़ी से भेजे जा रहे थे, तभी एक पशु मालिक नानू यादव साथियों के साथ पहुंचा और विवाद करने लगा। उसने सुपरवाइजर और कर्मचारियों को धमकाते हुए कहा कि वह आज किसी की हत्या कर देगा। इसके बाद जबरदस्ती पशु गाड़ी से निकालने लगा। मामले में टीम ने वरिष्ठ अफसरों को सूचित किया। इसके बाद थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई।

पंडित प्रदीप मिश्रा की कथा को लेकर ट्रैफिक मैनेजमेंट की तैयारी शुरू

सिटी चीफ इंदौर।

इंदौर। मध्यप्रदेश के सीहोर जिले में स्थित कुबेरेश्वर धाम में 25 फरवरी से 3 मार्च तक पंडित प्रदीप मिश्रा द्वारा शिवमहापुराण कथा का आयोजन किया जाएगा, जिसमें लाखों श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना है। दो साल पहले आयोजित रुद्राक्ष महोत्सव के दौरान भारी भीड़ के कारण सड़क पर लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा था। इसे ध्यान में रखते हुए इस बार कार्यक्रम में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए सुरक्षा और यातायात व्यवस्था को दुरुस्त करने के उद्देश्य से कुबेरेश्वर धाम क्षेत्र के मार्गों में विशेष परिवर्तन किए गए हैं। बुधवार 26 फरवरी को महाशिवरात्रि आएगी जिससे यहां पर और भी अधिक भीड़ आने की उम्मीद है। शिवमहापुराण कथा के दौरान मध्य प्रदेश सहित अन्य राज्यों से आने वाले श्रद्धालुओं की

भारी संख्या में उपस्थिति को देखते हुए प्रशासन ने भोपाल और इंदौर के बीच यातायात को सुचारू बनाए रखने के लिए 24 फरवरी सुबह 6 बजे से मार्गों में परिवर्तन किया है। भोपाल से इंदौर जाने वाले भारी वाहनों को श्यामपुर, ब्यावरा होते हुए इंदौर (तूमडा दोराहा जोड़ के माध्यम से) भेजा जाएगा। इसी प्रकार, इंदौर से भोपाल आने वाले भारी वाहनों को देवास से ब्यावरा, श्यामपुर होते हुए भोपाल जाने की अनुमति दी गई है। हल्के वाहनों और यात्री बसों के लिए भी विशेष रूट प्लान तैयार किया गया है। भोपाल से आष्टा, देवास और इंदौर जाने वाले छोटे वाहन और यात्री बसें सीहोर स्थित क्रिसेंट चौराहा से भाऊखेड़ी जोड़ और अमलाहा होते हुए इंदौर पहुंचेंगी। इसी तरह, इंदौर से भोपाल या सीहोर आने वाले वाहन अमलाहा से भाऊखेड़ी जोड़ और क्रिसेंट चौराहा होकर सीहोर और भोपाल जा सकेंगे। हालांकि, केवल कुबेरेश्वर धाम जाने वाले वाहनों को ही सीधे हाईवे से गुजरने की अनुमति होगी, जबकि अन्य सभी वाहनों को डायवर्सन मार्ग से संचालित किया जाएगा। आयोजन में लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने की उम्मीद है, जिससे यातायात पर भारी प्रभाव पड़ सकता है। प्रशासन ने भीड़ नियंत्रण और सुगम यातायात प्रबंधन के लिए विशेष इंतजाम किए हैं, ताकि किसी को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो। श्रद्धालुओं से अपील की गई है कि वे प्रशासन द्वारा तय किए गए मार्गों का पालन करें और यात्रा के दौरान यातायात नियमों का ध्यान रखें।

धर्मांतरण का आरोप, दो महिलाओं सहित चार पर केस

सिटी चीफ इंदौर।

इंदौर। इंदौर के संयोगितागंज इलाके में रविवार को एक कॉलोनी के गार्डन के पास धर्मांतरण की सूचना पर हिंदूवादी संगठन के कार्यकर्ता पहुंच गए और जमकर हंगामा किया। उन्होंने कार्यक्रम बंद करवाया, जिसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने देर शाम हिंदूवादी संगठनों की शिकायत के आधार पर कार्यक्रम में शामिल दो ईसाई महिलाओं सहित चार लोगों पर मामला दर्ज किया। संयोगितागंज पुलिस ने हिंदूवादी नितीन गोयल की शिकायत पर शीला सबरी मैथ्यू, अशुमन (पुत्र शंकर पंजवानी) निवासी बंगाली कॉलोनी, फ्रसीना नेलसन (निवासी स्कीम नंबर 78) और प्रभा (पुत्री राजेश यादव) निवासी देवनगर के खिलाफ धर्मांतरण की धाराओं में केस दर्ज किया है। जानकारी के मुताबिक, नितीन गोयल और अन्य स्थानीय निवासियों ने बताया कि, गार्डन नंबर 1 में मैजिक वाहन के जरिए करीब 50 बच्चों को लाया गया था। जब उन्होंने बच्चों की भीड़ देखी और अंदर गए, तो वहां मौजूद ईसाई महिलाएं उन्हें प्रार्थना करवा रही थीं। बताया जा रहा है कि, वे बच्चों से कह रही थीं कि यीशु ही उनके भगवान हैं, इसलिए राम और कृष्ण की पूजा करना बंद कर दो। इन महिलाओं ने बच्चों के लिए कॉपी-किताबें, कुछ गिफ्ट और नाश्ता भी मंगवाया था, जिसका स्थानीय निवासियों ने विरोध किया। जब बच्चों से पूछताछ की गई तो

उन्होंने बताया कि, ये लोग उनकी स्कूल फीस सहित अन्य खर्च भी उठा रहे हैं। पूरी प्रक्रिया धर्म परिवर्तन से जुड़ी थी। इस मामले की जानकारी हिंदूवादी संगठनों को दी गई, जिसके बाद पुलिस को मौके पर बुलाया गया। क्रिश्चियन समाज के लोगों का कहना है कि, उन्होंने बच्चों के मेडिकल परीक्षण के उद्देश्य से बाल संसद आयोजित की थी। इस सभा में शामिल अधिकांश बच्चे पहले भी ऐसे कार्यक्रमों का हिस्सा रह चुके थे। कई बच्चे अपनी माताओं के साथ पहुंचे थे। हालांकि, हिंदूवादी संगठनों के विरोध और हंगामे के बीच बच्चे कार्यक्रम छोड़कर चले गए। बाद में हिंदूवादी संगठन और स्थानीय रहवासी थाने पहुंचे और धर्मांतरण के आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग की।

पद संभाला पर कुर्सी पर नहीं बैठ रहे भाजपा शहर अध्यक्ष

सिटी चीफ इंदौर।

इंदौर। भाजपा इंदौर महानगर के अध्यक्ष बने सुमित मिश्रा को आज 20 दिन पूरे हो चुके हैं, लेकिन वे अभी तक अपनी कुर्सी पर नहीं बैठे हैं। संगठन का काम वे पूरी तरह संभाल चुके हैं, लेकिन किसी और कुर्सी से ही बैठकर फैसले ले रहे हैं। इसे लेकर पार्टी के भीतर और कार्यकर्ताओं के बीच चर्चाएं तेज हो गई हैं कि आखिर मिश्रा अपनी कुर्सी पर क्यों नहीं बैठ रहे। पहले इस देरी का कारण शुभ मुहूर्त बताया जा रहा था, लेकिन अब तो विधिवत पूजा-

पाठ भी हो चुका है। इसके बावजूद वे अभी तक नगर अध्यक्ष की कुर्सी ग्रहण करने से बच रहे हैं। जब उनसे इस संबंध में सवाल किया गया तो उन्होंने इसे बेवजह की चर्चा करार दिया और कहा कि राजनीति में हर बात पर हल्ला मचता है, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। संगठन का काम पहले ही शुरू कर दिया है, और अभी हमारा पूरा फोकस आजीवन सहयोग निधि अभियान पर है। 30 जनवरी को भाजपा प्रदेश संगठन ने नगर और ग्रामीण अध्यक्ष के रूप में सुमित मिश्रा और श्रवणसिंह चावड़ा की नियुक्ति की थी। चावड़ा ने 11 फरवरी को विधि-विधान से पूजन कर अपनी कुर्सी ग्रहण कर ली, लेकिन मिश्रा अब भी नगर अध्यक्ष की कुर्सी से दूरी बनाए हुए हैं। हालांकि, उन्होंने कार्यालय में रामायण पाठ और कन्या पूजन का आयोजन जरूर किया, लेकिन कुर्सी पर बैठने का कोई संकेत नहीं दिया। इसे लेकर कार्यकर्ताओं और पार्टी पदाधिकारियों के बीच सवाल उठ रहे हैं कि आखिर मिश्रा किस विशेष मुहूर्त का इंतजार कर रहे हैं? बताया जा रहा है कि वे कुछ वरिष्ठ नेताओं की उपस्थिति चाहते हैं, जिनके सामने वे अपनी कुर्सी ग्रहण करेंगे। हालांकि, मिश्रा ने इस मुद्दे पर ज्यादा कुछ कहने से बचते हुए सिर्फ इतना कहा कि जब विधायक रमेश मेंदोला नगर अध्यक्ष थे, तो वे अधिकतर फील्ड में ही सक्रिय रहे और कुर्सी पर नहीं बैठे। वहीं, गोपीकृष्ण नेमा भी नगर अध्यक्ष रहते हुए कभी अपनी कुर्सी पर नहीं बैठे थे। इसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए वे भी कार्यकताओं के बीच रहकर संगठन का काम कर रहे हैं।

प्रयागराज जाने वाली 16 ट्रेनें निरस्त, यात्रियों की बढ़ेगी परेशानी

सिटी चीफ इंदौर।

भोपाल। भोपाल रेल मंडल से ट्रेन की यात्रा करने वाले यात्रियों की परेशानी बढ़ने वाली है। खासकर महाकुंभ प्रयागराज जाने वाले यात्री और परेशान हो सकते हैं। दरअसल, भोपाल रेलवे प्रशासन ने संधारण संबंधित कारणों से भोपाल मंडल से शुरू और गुजरने वाली कई यात्री गाड़ियों को अस्थायी रूप से निरस्त करने का निर्णय लिया है। इसमें भोपाल-ग्वालियर एक्सप्रेस और गोरखपुर-छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस एक्सप्रेस जैसी ट्रेनें शामिल हैं। वहीं, उत्तर मध्य रेलवे प्रयागराज मंडल में महाकुंभ मेला-2025 के चलते परिचालनिक कारणों से भोपाल मंडल से होकर गुजरने वाली 16 ट्रेनें अपने प्रारंभिक स्टेशन से निरस्त रहेंगी।

28 फरवरी तक ये गाड़ियां रहेंगी निरस्त

-गाड़ी संख्या 12197 भोपाल-ग्वालियर एक्सप्रेस 28 फरवरी तक अपने प्रारंभिक स्टेशन से निरस्त रहेगी।

-गाड़ी संख्या 12198 ग्वालियर-भोपाल एक्सप्रेस 28 फरवरी 2025 तक अपने प्रारंभिक स्टेशन से निरस्त रहेगी।

ये ट्रेनें आज रहेंगी निरस्त

- गाड़ी संख्या 19045 सूरत-छपरा तापी गंगा एक्सप्रेस 19 फरवरी 2025 को अपने प्रारंभिक स्टेशन से निरस्त रहेगी।

- गाड़ी संख्या 19483 अहमदाबाद-बरौनी एक्सप्रेस 19 फरवरी 2025 को अपने प्रारंभिक स्टेशन से निरस्त रहेगी।

- गाड़ी संख्या 01025 दादर-बलिया त्रि-साप्ताहिक एक्सप्रेस स्पेशल ट्रेन 19 फरवरी 2025 को अपने प्रारंभिक स्टेशन से निरस्त रहेगी।

- गाड़ी संख्या 11055 लोकमान्य तिलक टर्मिनस-गोरखपुर एक्सप्रेस 19 फरवरी 2025 को अपने प्रारंभिक स्टेशन से निरस्त रहेगी।

-गाड़ी संख्या 12428 आनंद विहार टर्मिनस-रीवा एक्सप्रेस 19 फरवरी 2025 को अपने प्रारंभिक स्टेशन से निरस्त रहेगी।

-गाड़ी संख्या 12427 रीवा-आनंद विहार टर्मिनस एक्सप्रेस 19 फरवरी 2025 को अपने प्रारंभिक स्टेशन से निरस्त रहेगी।

कल ये ट्रेनें रहेंगी निरस्त

- गाड़ी संख्या 22912 हावड़ा-इंदौर क्षिप्रा एक्सप्रेस 20 फरवरी 2025 को अपने प्रारंभिक स्टेशन से निरस्त रहेगी।

-गाड़ी संख्या 01028 गोरखपुर-दादर एक्सप्रेस स्पेशल 20 फरवरी 2025 को अपने प्रारंभिक स्टेशन से निरस्त रहेगी।

-गाड़ी संख्या 12427 रीवा-आनंद विहार टर्मिनस एक्सप्रेस 20 फरवरी 2025 को अपने प्रारंभिक स्टेशन से निरस्त रहेगी।

- गाड़ी संख्या 11060 छपरा-लोकमान्य तिलक टर्मिनस एक्सप्रेस 20 फरवरी 2025 को अपने प्रारंभिक स्टेशन से निरस्त रहेगी।

21 फरवरी को ये ट्रेनें रहेंगी निरस्त

-गाड़ी संख्या 19046 छपरा-सूरत तापी गंगा एक्सप्रेस 21 फरवरी 2025 को अपने प्रारंभिक स्टेशन से निरस्त रहेगी।

-गाड़ी संख्या 19484 बरौनी-अहमदाबाद एक्सप्रेस 21 फरवरी 2025 को अपने प्रारंभिक स्टेशन से निरस्त रहेगी।

-गाड़ी संख्या 01026 बलिया-दादर त्रि-साप्ताहिक एक्सप्रेस स्पेशल ट्रेन 21 फरवरी 2025 को अपने प्रारंभिक स्टेशन से निरस्त रहेगी।

- गाड़ी संख्या 11056 गोरखपुर-लोकमान्य तिलक टर्मिनस एक्सप्रेस 21 फरवरी 2025 को अपने प्रारंभिक स्टेशन से निरस्त रहेगी।

प्रभावित ट्रेनों का विवरण

-27 फरवरी 2025 तक डॉ. अंबेडकर नगर से प्रस्थान करने वाली ट्रेन संख्या 14115 डॉ. अंबेडकर नगर-प्रयागराज एक्सप्रेस खजुराहो स्टेशन पर शॉर्ट टर्मिनेट होगी तथा खजुराहो से प्रयागराज के मध्य- निरस्त रहेगी।

ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के लिए बनाई जा रही टेंट सिटी का 60% काम पूरा

सिटी चीफ इंदौर।

भोपाल। राजधानी भोपाल में 24 और 25 फरवरी को होने वाले ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट (जीआईएस) को लेकर तैयारियां जोरों पर है। मेहमानों के लिए भोपाल के कलिया सोत डेम पास 108 टेंट सिटी बन रही है। इनमें 5 स्टार होटल्स जैसी सारी सुविधाएं रहेंगी। एयर कंडिशनर से लेकर डबल बेड, लाइटिंग, वॉक के लिए बागीचा रहेगा, ताकि वे प्रकृति को करीब से जान सकेंगे। कलियासोत ग्राउंड के ठीक पीछे डैम और आसपास हरियाली का आकर्षक नजारा दिखाई देता है। टेंट सिटी को बना रहे कंपनी का दावा है कि करीब 60 से 70त्न काम पूरा हो गया है। 22 फरवरी के पहले इसे पूरी तरह तैयार कर दिया जाएगा। 11 फरवरी से टेंट सिटी तैयार हो रही है। राजस्थान की एक फर्म टेंट सिटी तैयार कर रही है। कंपनी के चक्रवर्ती सिंह ने बताया कि, डेढ़ सौ से ज्यादा कारीगर और मजदूर टेंट सिटी बनाने में लगे हैं। इनमें ग्राफिक्स, पार्क, टेंट आदि काम वे कर रहे हैं। कलाकार जयपुर, मुंबई और भोपाल के हैं।

होटल जैसी लग्जरी सुविधाएं मिलेंगी

टेंट सिटी में होटल जैसी लग्जरी सुविधाएं ही रहेंगी। अंदर डबल बेड, एयर कंडिशन रहेगा तो बाहर सिक्योरिटी के इंतजाम और डॉक्टरों की टीम 24 घंटे मौजूद रहेगी। 3 दिन के लिए ये टेंट सिटी बनेगी। इनमें विदेशी मेहमान ही रुकेंगे। ताकि, वे प्रकृति भरे माहौल में रहे। टेंट सिटी से समिट स्थल तक लाने ले जाने के लिए गाड़ियां मौजूद रहेंगी।

एमपीटी के देखरेख में बन रही टेंट सिटी

दरअसल पहले दो टेंट सिटी कलियासोत और केरवा डैम किनारे बनाने पर मंथन चल रहा था। ताकि, मेहमान प्रकृति के नजारे भी देख सकें, लेकिन बाद में पं. खुशीलाल शर्मा आयुर्वेद कॉलेज के पास कलियासोत ग्राउंड को ही तय कर लिया गया। यही पर सभी 108 टेंट की बड़ी सिटी बनाई जा रही है। मप्र राज्य पर्यटन विकास निगम की देखरेख में टेंट सिटी बनकर कम्प्लीट हो रही है।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने की बैठक

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने मंगलवार को समत्व में 24 एवं 25 फरवरी को होने वाली ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के लिए गठित शीर्ष समिति की बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 24 फरवरी को सुबह करीब 10 बजे दो दिवसीय जीआईएस का शुभारंभ करेंगे। साथ ही मध्यप्रदेश की सभी नवीनतम औद्योगिक नीतियों की लॉन्चिंग भी करेंगे। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी जीआईएस परिसर में स्थापित किए जाने वाले एमपी एक्सपीरियंस जोन का अवलोकन भी करेंगे।इस जोन में इमर्सिव डिजिटल वॉक-थ्रू के रूप में मध्यप्रदेश की विरासत, अब तक की प्रगति का प्रदर्शन किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि जीआईएस को भव्य, सुव्यवस्थित और परिणामदायी बनाने के लिए सभी विभाग बेहतर समन्वय एवं सामंजस्य से कार्य करें।

आयोजन को बनाएं ऐतिहासिक

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने निर्देशित किया कि ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट मध्यप्रदेश की अर्थव्यवस्था को मजबूती देने और देश-विदेश के निवेशकों को आकर्षित करने के उद्देश्य से की जा रही है। इसीलिए आयोजन को ऐतिहासिक बनाने के लिए सभी तैयारियां व्यापक स्तर पर की जाएं। जीआईएस के आयोजन में प्रबंधन संबंधी कोई भी कमी न रहे।उन्होंने ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट की तैयारियों की विस्तार से समीक्षा की। साथ ही अधिकारियों को निर्देश दिए कि निवेशकों को सहज आकर्षित करने के लिए राज्य की सभी निवेशक हितैषी औद्योगिक नीतियों, म.प्र. में उद्योगों के लिए उपलब्ध व्यापक अधोसंरचनाओं और संभावनाओं को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया जाए। उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश को इंडस्ट्री फ्रेंडली स्टेट बनाने के लिए निवेशकों को वांछित सभी जरूरी सहायता और सुविधाएं मुहैया कराई जाएं।

भारतीय परंपरा से स्वागत किया जाए

इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि जीआईएस में देश-विदेश से भोपाल आने वाले निवेशक हमारे विशेष अतिथि हैं, इसलिए उनका स्वागत और अभिनंदन विशुद्ध भारतीय आतिथ्य परंपरा से किया जाए। इन दो दिनों को स्मरणीय बनाने के लिए मध्यप्रदेश की संस्कृति, यहां की सत्कार परंपरा, विभिन्न कला उत्पादों सहित यहां के खान-पान, व्यंजन आदि का विशेष रूप से प्रदर्शन किया जाए, जिससे निवेशक दो दिन मध्यप्रदेश में रहने के शानदार अनुभव लेकर जाएं। मुख्यमंत्री ने भोपाल के तालाबों और पूरे शहर का आकर्षक सौंदर्यीकरण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि बड़ी झील में पाल-नौकायन और ई-बैटरी से चलित नौकाओं का संचालन किया जाए, जिससे निवेशक और दूसरे प्रतिभागी भोपाल के अनुपम प्राकृतिक सौंदर्य का लुत्फ ले सकें।

60 से अधिक देश के प्रतिभागी आएंगे

बैठक में बताया गया कि जीआईएस में 60 से अधिक देश के प्रतिभागी शामिल होंगे। इसमें जिम्बाब्वे के उप मंत्री सहित 10 देशों के राजदूत, 8 देशों के उच्चायुक्त, 7 देशों के काउंसलेट जनरल सहित कुल 133 विदेशी प्रतिभागी शामिल होंगे। जीआईएस में देश के प्रमुख उद्योगपतियों सहित भारत की अग्रणी कंपनियों को 300 से अधिक अध्यक्ष, एमडी और सीईओ भी प्रतिभागी के रूप में शामिल होंगे। जीआईएस में 6 विभागीय सम्मेलन, 6 कंट्री सेशन एवं 10 सेक्टोरल सत्र भी आयोजित किए जाएंगे।

31 हजार से अधिक रजिस्ट्रेशन

बताया गया कि जीआईएस में अब तक विभिन्न श्रेणियों में 31 हजार 659 प्रतिभागियों ने पंजीयन कराया है। इनमें से 18 हजार 736 से अधिक प्रतिभागियों ने भोपाल आने की सहमति भी दी है। अधिकारियों ने यह भी बताया कि जीआईएस आयोजन परिसर में ही एक जिला-एक उत्पाद श्रेणी के सभी उत्पादों का प्रदर्शन किया जाएगा। इसके लिए एक पूरा गांव तैयार किया जा रहा है। परिसर में पारम्परिक मिट्टी के बर्तनों, टेराकोटा हस्तनिर्मित मिट्टी की कलाकृतियां एवं म.प्र. की प्रख्यात मूर्तिकला के शिल्पों का भी विशेष प्रदर्शन किया जाएगा।

चलती ट्रेन में डाका डालने वाले मोहर सिंह पारदी ने एसपी को भेजा मैसेज

सिटी चीफ इंदौर।

भोपाल/गुना। कुख्यात अपराधी मोहर सिंह पारदी एक बार फिर से सुर्खियों में है। उसने एक युवक को बेरहमी से प्रताड़ित किया है। इस घटना का वीडियो वायरल हो गया है। पारदी ने गुना के एसपी संजीव सिन्हा को एक वीडियो संदेश भी भेजा है। इसमें उसने अपनी करतूत का कथित रूप से औचित्य बताया है। पारदी 2016 में तमिलनाडु ट्रेन डकैती जैसी लगभग 60 आपराधिक घटनाओं में शामिल रहा है। वह फिलहाल फरार है। 20 जनवरी को एक युवक खाना खरीदने जा रहा था। मोहर सिंह पारदी और उसके साथियों ने उसका अपहरण कर लिया। मिथुन, नरेंद्र पारदी और अन्य साथी भी इस घटना में शामिल थे। उन्होंने युवक को गढ़ला गांव ले जाकर उसे नंगा किया और बेरहमी से पीटा। उसके गुप्तांगों पर प्लास लगाया गया और उस पर पानी डाला गया। जूते से भी मारा गया। इस पूरी घटना का वीडियो उसके एक साथी ने बनाया, जो अब वायरल हो रहा है।

एसपी को भेजा वीडियो

वीडियो वायरल होने के बाद, मोहर सिंह पारदी ने एसपी सिन्हा को एक वीडियो संदेश भेजा। यह संदेश उसने एक मीडियाकर्मी के माध्यम से भेजा। इसमें उसने अपनी इस बर्बरता को सही ठहराने की कोशिश की है। उसने कहा कि अगर कोई मेरी पत्नी या बेटी को बार-बार फोन करता है, तो मुझे गुस्सा आएगा। समझाने के बाद भी अगर वो व्यक्ति नहीं समझता है, तो मैं क्या करूं? इसलिए मैंने उसे पीटा, नंगा किया और सजा दी। जो मुझे सही लगा, मैंने वो किया। बस इतना ही कहना है साहब। नमस्ते।

आठ फरवरी को पारदी के चंगुल से भागा

8 फरवरी को पीड़ित युवक किसी तरह पार्दी के चंगुल से भाग निकला। उसने अपनी मां को आपबीती सुनाई। मां ने कोतवाली थाने में मोहर और उसके छह साथियों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। कालू पार्दी, मिथुन पार्दी और नरेंद्र पारदी भी आरोपियों में शामिल हैं।

मनरेगा को लेकर दिग्विजय सिंह ने शिवराज को लिखा पत्र

सिटी चीफ इंदौर।

भोपाल। मध्यप्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान को एक पत्र लिखकर मध्यप्रदेश में महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना के तहत 266 कार्यों को करने की मांग की है। इस पत्र में उल्लेख किया गया है कि भारत सरकार ने वर्ष 2023 में मध्यप्रदेश में महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना के तहत 266 कार्य करने के निर्देश दिए थे, लेकिन मध्यप्रदेश शासन के पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने केवल 24 कार्यों को ही मंजूरी दी है। दिग्विजय सिंह ने कहा है कि इस योजना के तहत केवल 24 कार्यों को मंजूरी देने से ग्रामीण क्षेत्रों के विकास पर दुष्प्रभाव पड़ेगा और ग्रामीण क्षेत्र के मजदूरों को पर्याप्त मात्रा में मजदूरी नहीं मिलेगी, जिससे उन्हें पलायन करने को मजबूर होना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना के तहत कार्यों को करने से ग्रामीण क्षेत्रों का विकास होगा और ग्रामीण क्षेत्रों के मजदूरों को रोजगार के अवसर मिलेंगे। उन्होंने आगे कहा कि महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना के तहत कार्यों को करने से ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर पैदा होते हैं और ग्रामीण क्षेत्रों का विकास होता है। इस योजना के तहत कार्यों को करने से ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कें, पुल, तालाब, और अन्य आधारभूत संरचनाएं बनाई जाती हैं, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों का विकास होता है। दिग्विजय सिंह ने केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान से अनुरोध किया है कि वे इस मामले में आवश्यक कार्यवाही करें और मध्यप्रदेश में महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना के तहत 266 कार्यों को करने के निर्देश दें।

कांग्रेस ने की पूर्व मंत्री भूपेंद्र सिंह को सह आरोपी बनाने की मांग

भोपाल। परिवहन विभाग के पूर्व आरक्षक सौरभ शर्मा की परिवहन विभाग में अनुकंपा नियुक्ति को लेकर कांग्रेस ने पूर्व मंत्री भूपेंद्र सिंह को सह आरोपी बनाने की मांग की है। विधानसभा में उप नेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे के नेतृत्व में कांग्रेस का एक प्रतिनिधिमंडल लोकायुक्त कार्यालय पहुंचा और लोकायुक्त डीजी जयदीप प्रसाद को शपथ पत्र के साथ शिकायत सौंपी है। प्रतिनिधिमंडल में विधायक आरिफ मसूद, पूर्व मंत्री पीसी शर्मा, मुकेश नायक, शहर अध्यक्ष प्रवीण सक्सेना शामिल थे। हेमंत कटारे ने आरोप लगाया कि परिवहन विभाग के पूर्व आरक्षक सौरभ शर्मा के मामले में पूर्व परिवहन मंत्री भूपेंद्र सिंह की अहम भूमिका है। लोकायुक्त डीजी से मुलाकात के बाद उप नेता प्रतिपक्ष ने मीडिया से कहा कि लोकायुक्त डीजी से हमारा डेलीगेशन मिला। हमने उनसे कहा है कि सौरभ शर्मा के मामले में पूरा मप्र कलंकित हो रहा है।

मप्र में फिर बदला मौसम, भोपाल-इंदौर में तेज धूप, मुरैना-भिंड में बूंदाबांदी

सिटी चीफ इंदौर।

भोपाल। मध्यप्रदेश में मौसम फिर से बदल गया है। भोपाल, इंदौर-उज्जैन में मंगलवार सुबह से ही तेज धूप खिली, जबकि ग्वालियर-चंबल संभाग में कहीं-कहीं हल्की बारिश हुई है। सुबह भिंड और मुरैना में बौछारें गिरीं। वहीं, दोपहर में ग्वालियर, दतिया, श्योपुर और निवाड़ी जिलों में हल्की बारिश होने का अलर्ट है।

मुरैना में बादलों के बीच सुबह 11.30 बजे हल्की बूंदाबांदी शुरू हो गई। इससे मौसम में ठंडक घुल गई। भिंड में भी बादल छाए रहे। इधर, भोपाल में सुबह से ही तेज धूप खिली रही। इस कारण लोग धूप से बचने के जतन करते रहे। मौसम विभाग के अनुसार, मध्यप्रदेश के ऊपर एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन एक्टिव है। इसका हल्का असर ग्वालियर-चंबल में दिखाई दे रहा है। इससे पहले सोमवार को नर्मदापुरम, खंडवा, मंडला और सिवनी सबसे गर्म रहे। वहीं, भोपाल-उज्जैन में भी तापमान 31 डिग्री से अधिक रहा ठंड का असर खत्म होते ही भोपाल समेत प्रदेश के कई शहरों में स्कूलों की टाइमिंग बदल गई है। अब स्कूल सुबह 9 बजे की बजाय 7.30 बजे से लग रहे हैं। वहीं, दिन में जल्दी छुट्टी हो रही है। मौसम वैज्ञानिक रैकवार ने बताया, अगले 4 दिन तक ऐसा ही मौसम रहेगा। 19 फरवरी से एक वेस्टर्न डिस्टरबेंस जरूर एक्टिव हो रहा है। इसके असर से 22-23 फरवरी से पारे में दो से तीन डिग्री की गिरावट हो सकती है। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक फरवरी में कई वेस्टर्न डिस्टरबेंस एक्टिव होते हैं। अबकी बार भी ऐसा ही है। इस वजह से पारे में उतार-चढ़ाव की स्थिति बनी रहेगी। फिलहाल बारिश होने के आसार नहीं है।19 फरवरी को दिन-रात के तापमान में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी।

सीएम मोहन यादव की नई टीम, लगभग 15 महीनों में दूसरा फेरबदल

सिटी चीफ इंदौर।

भोपाल। मध्यप्रदेश की डॉ. मोहन यादव सरकार को एक साल 2 महीने का समय हो गया है। इस बीच, उन्होंने दूसरी बार मंत्रालय में अफसरों की जमावट की है। अब इन अधिकारियों को नए सिरे से काम सौंपा गया है। यह दूसरा मौका है, जब डॉ. मोहन यादव ने 15 महीनों के भीतर एक बार फिर अपनी टीम में फेरबदल किया है। इस टीम में सबसे प्रमुख नाम भारतीय प्रशासनिक सेवा के प्रमोटी अफसर चंद्रशेखर वालिम्बे का है। मुख्यमंत्री कार्यालय में अपर सचिव यानि एडिशनल सेक्रेट्री वालिम्बे को सामान्य प्रशासन विभाग, कार्मिक, गृह, जनसंपर्क, पीडब्ल्यूडी, पीएचई, स्कूल शिक्षा, लॉ, जनजातीय जलसंशाधन, वाणिज्यिक कर, खाद्य एवं बाल विकास संभाग के समन्वय का काम सौंपा गया है। शहरी विकास, स्वास्थ्य विभाग, ट्रांसपोर्ट जैसे कई बड़े काम उन्हें सौंपे गए हैं। वालिम्बे को दिये गए कार्यों को देखें तो पता चलता है कि कई बड़े अधिकारी उनसे पिछड़ गए।

इन अधिकारियों से आगे निकले वालिम्बे

डायरेक्ट भर्ती के आईएएस सिवि चक्रवर्ती एम. और टी. इलैया राजा से आगे वालिम्बे निकल गए हैं।

इस फेरबदल के साथ सीएम डॉ. मोहन यादव ने सीधा मैसेज दिया है कि जो अफसर ईमानदारी और मेहनत से काम करेगा, उसका कद भी बढ़ा रहेगा। आपको बता दें कि मध्यप्रदेश के प्रशासनिक इतिहास में संभवत- ऐसा पहली बार है, जब वालिम्बे के रूप में पहली बार सीधे माने जाने वाले अफसर को बड़े काम दिए गए हैं। आपको बता दें कि चंद्रशेखर वालिम्बे प्रमोट होकर आईएएस तो बन गए, लेकिन उन्हें फील्ड पोस्टिंग अब तक नहीं मिली है। वे कलेक्टर नहीं बन पाए। बताया जाता है कि वे काफी सीधे—साधे और काम करने वाले अधिकारी हैं। उनके अधिकांश बैचमेट कलेक्टर बन गए, यहां तकि उनकी पत्नी भावना वालिम्बे भी कलेक्टर पदस्थ रही हैं।

सम्पादकीय

कम वर्किंग डे वाले छोटे लोकसभा और विधानसभा सत्र का मुद्दा

पिछले कुछ वर्षों में लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के सत्र लगातार कम होते जा रहे हैं। यह मुद्दा लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने उठाया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने कम समय के सत्र और सदन में हंगामे पर चिंता जाहिर की है। लोकसभा और राज्यसभा से लेकर विधानसभा एवं विधान परिषद तक, सदन के बार-बार स्थगित होने से इसकी कार्यवाही प्रभावित होती है।

पिछले कुछ वर्षों में लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के सत्र लगातार कम होते जा रहे हैं। यह मुद्दा लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने उठाया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने कम समय के सत्र और सदन में हंगामे पर चिंता जाहिर की है। लोकसभा और राज्यसभा से लेकर विधानसभा एवं विधान परिषद तक, सदन के बार-बार स्थगित होने से इसकी कार्यवाही प्रभावित होती है। बिड़ला ने जनवरी में बिहार में कहा था कि 1954 में सदनों को बार-बार स्थगित होने से बचाना एक चुनौती का काम था। यह आज भी एक चुनौती ही बना हुआ है। उन्होंने सत्रों की अवधि बढ़ाने पर जोर देते हुए सदन की गरिमा बढ़ाने के लिए सभी नेताओं, पार्टियों और संबंधित पदाधिकारियों को साथ आने की अपील की। बिड़ला ने फरवरी में भी महाराष्ट्र विधानसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों को संबोधित करते हुए फिर यह यह मुद्दा उठाया। ओम बिड़ला अकेले ऐसे व्यक्ति नहीं हैं जिन्होंने विधायी सत्रों की घटती अवधि पर प्रकाश डाला है। तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के सांसद डेरेक ओ ब्रायन ने बजट सत्र के दौरान राज्यसभा में एक निजी विधेयक पेश किया था , जिसमें एक निश्चित कैलेंडर के साथ हर साल संसद में कम से कम 100 दिन की बैठकें करने की बात कही गई थी। राज्यों में भी, कम वर्किंग डे वाले छोटे विधानसभा सत्र को मुद्दा बनाया गया है। उदाहरण के लिए, मध्यप्रदेश में कांग्रेस ने इस महीने की शुरुआत में 9 दिनों के बजाय 21 दिनों के लंबे बजट सत्र की मांग की। गोवा में, विपक्षी दलों ने पिछले दो दिवसीय शीतकालीन सत्र का विरोध किया। इसे संविधान का मजाक और लोकतंत्र की हत्या कहा गया। पीआरएस लेजिस्लेटिव रिसर्च, लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के आंकड़ों से पता चलता है कि हाल के वर्षों में विधानसभाओं के वर्किंग डे की संख्या में काफी गिरावट आई है। पीआरएस लेजिस्लेटिव रिसर्च के आंकड़ों से पता चलता है कि पहली लोकसभा (1952 से 1957) के कार्यकाल के दौरान प्रतिवर्ष औसतन 135 बैठक दिवसों की तुलना में, 17वीं लोकसभा (2019 से 2024) में प्रतिवर्ष औसतन केवल 55 बैठक दिवस ही हुए। 17वीं लोकसभा की औसत वार्षिक बैठकें सबसे कम 55 रहीं, जो 16वीं लोकसभा की 66 और 15वीं लोकसभा की 71 बैठकों से कम है। उस दौरान कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सत्ता में थी। हालांकि, हाल के वर्षों में छोटे सत्रों में पिछले लंबे सत्रों की तुलना में अधिक विधेयक पारित किए गए हैं। उदाहरण के लिए, 17वीं लोकसभा ने 14वीं लोकसभा (2004 से 2009) की तुलना में 40 अधिक विधेयक पारित किए जबकि हर साल औसतन 10 दिन कम बैठकें होती हैं। विधेयकों को सीमित बहस के साथ या समितियों को भेजे बिना ही पारित कर दिया जाता है। जिन 22 राज्यों के विधानसभा सत्रों की अवधि के आंकड़े उपलब्ध हैं, उनमें से कम से कम तीन कार्यकालों के दौरान केवल दो राज्यों में औसत वार्षिक बैठक के दिनों में वृद्धि देखी गई है जबकि शेष 20 राज्यों में गिरावट देखी गई है। उदाहरण के लिए, 13वीं गुजरात विधानसभा (2012 से 2017) में सालाना औसतन 28 बैठक दिन दर्ज किए गए। 14वीं विधानसभा (2017 से 2022) के लिए यही आंकड़ा 29 रहा, जो कि मामूली वृद्धि है। 14वीं (2013 से 2018) और 15वीं (2018 से 2023) राजस्थान विधानसभाओं के आंकड़े गुजरात विधानसभा के आंकड़ों के बिल्कुल समान हैं। हालांकि, दोनों राज्यों के लिए मौजूदा विधानसभा कार्यकाल में बैठक दिनों में कमी देखी गई है जो गुजरात में 25 और राजस्थान में 27 रही। बैठक के दिनों की संख्या में सबसे बड़ी गिरावट तेलंगाना में हुई, जहां पहली (2014 से 2018) और दूसरी (2018 से 2023) विधानसभाओं के बीच यह 26 से 15 तक 42.3 प्रतिशत गिर गई। मध्यप्रदेश दूसरे स्थान पर था, जहां 14वीं (2013 से 2018) से 15वीं विधानसभा (2018 से 2023) तक 27 से 16 दिन तक की गिरावट आई, यानी 40.7 प्रतिशत की गिरावट। महाराष्ट्र में, 13वीं विधानसभा (2014 से 2019) में 44 दिनों से 14वीं विधानसभा (2019 से 2024) में 27 दिनों तक की गिरावट 38.6 प्रतिशत थी। दूसरी ओर, सबसे कम गिरावट 6.4 प्रतिशत केरल में हुई, जहां 13वीं विधानसभा (2011 से 2016) में औसतन 47 दिन प्रति वर्ष बैठकें हुईं, जबकि 14वीं विधानसभा (2016 से 2021) में यह घटकर 44 दिन रह गई। तीन राज्यों में, पिछले दो विधानसभा कार्यकालों की तुलना में मौजूदा विधानसभा के कार्यकाल में औसत वार्षिक बैठक दिवसों की संख्या अधिक या बराबर दर्ज की गई है।

स्वदेशी एआई बनाने का सुनहरा समय

किफायती इंजीनियरिंग में अपनी विशेषज्ञता को देखते हुए भारत एक ऐसा एआई मॉडल विकसित कर सकता है, जिसमें लागत काफी कम आए। मगर हमें इसे नागरिक-केंद्रित बनाना होगा, जो 1.4 अरब भारतीयों के लिए तैयार किया गया हो, ठीक डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना (डीपीआई) की तरह। जिस आसानी से भारतीय यूपीआई या डिजिटल पेमेंट सुविधा का लाभ ले रहे हैं, ठीक उसी तरह से भारत का अपना एआई भी होना चाहिए। निस्संदेह, इस राह में बहुत चुनौतियां हैं। यहां कई तरह के एआई मॉडल बनाने का अर्थ है कि हमें अधिक संसाधनों की जरूरत पड़ेगी।

बीते तीन वर्षों में कृत्रिम बुद्धिमत्ता, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) के विकास में दो खास क्षण आए हैं। पहला, नवंबर, 2022 में चैटजीपीटी की घोषणा, जिससे एआई युग की शुरुआत हुई और दूसरा, पिछली जनवरी में डीपसीक का ऐलान, जिसने महंगी व केंद्रीकृत एआई की धारणा को बदलकर इसके सस्ते और लोकतांत्रिक होने की मुनादी कर दी। आज भले ही चीन में विकसित डीपसीक की लागत महज 56 लाख डॉलर होने पर संदेह जताया जा रहा हो, पर यह एआई प्लेटफॉर्म दो वजहों से काफी अहम है - पहली, ओपेन-सोर्स मॉडल (सबके लिए मुफ्त में सुलभ) लगभग मालिकाना मॉडल (जिसकी खरीद-बिक्री संभव हो) जैसा अच्छा है और दूसरी, चीन के एआई मॉडल भी अमेरिकी मॉडल की तरह ही अच्छे हैं। यह सही है कि चैटजीपीटी सुविधा देने वाली कंपनी एनवीडिया के शेयर गिरने के बावजूद अमेरिकी निवेशकों ने बड़ी अमेरिकी टेक्नोलॉजी कंपनियों पर अपना भरोसा बनाए रखा है, मगर सवाल यह है कि दुनिया में निरंतर विकसित होते जा रहे एआई के आधारभूत मॉडलों का क्या होगा और इस प्रतिस्पर्द्धा में आज भारत कहां खड़ा होगा?

ये मॉडल अपनी विकास यात्रा में अंग्रेजी वर्ण 'के' की राह पर चल सकते हैं। 'के' आकार की अर्थव्यवस्था की चर्चा अर्थशास्त्री कोविड महामारी और लॉकडाउन के बाद से करते रहे हैं, जिसमें अर्थव्यवस्था का असमान पुनरोद्धार हो रहा है, यानी कुछ क्षेत्र, उद्योग या लोग तो तेजी से आगे बढ़ते हैं, जबकि बाकी क्षेत्रों में यथोचित विकास नहीं देखा जा रहा है। लगता है, लार्ज लैंग्वेज मॉडलों के साथ भी ऐसा ही हो रहा है। बड़े मॉडल अधिक महंगे होते जा रहे हैं, क्योंकि बड़ी कंपनियां एनवीडिया की नवीनतम ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट (जीपीयू) पर, बड़े मॉडलों के विकास और प्रशिक्षण देने पर, विशाल डेटा सेंटर और उनके संचालन के लिए जरूरी बिजली पर अरबों डॉलर खर्च कर रही हैं। मगर इस बीच, डीपसीक और किमी के1.5, क्रेन 2.5, डौबाओ 21.5 प्रो जैसे चीनी मॉडलों की बाढ़ आ गई। ओपन-सोर्स होने के कारण ये लागत को 'के' के निचले हिस्से की ओर ले जा रहे हैं। पुराने व कम चिप का इस्तेमाल करके ये मॉडल महज लाखों डॉलर में विकसित किए जा रहे हैं और लोकप्रिय हो रहे हैं। जाहिर है, अर्थशास्त्र की तरह ही यहां भी विकास का 'के-वक्र' बनेगा। बड़े खिलाड़ी एआई मॉडल को अधिक कुशल और सुपर इंटेलिजेंट बनाने की कोशिश करेंगे, जिसके कारण एआई आधारित सुविधाएं महंगी होंगी। मगर ध्यान रहे, भारत में ऐसी सुविधाओं का किफायती होना जरूरी है। एक पक्ष, एआई को महंगा बनाने की कोशिश करेगा। वहीं, दूसरा पक्ष, एआई को अत्यधिक लोकतांत्रिक बनाने और हर नागरिक तक इसे पहुंचाने का प्रयास करेगा, ताकि एक बड़ी आबादी की समस्याओं का निदान हो सके। किसी भी तकनीक का तभी सही लाभ मिल सकता है, जब वह आम आदमी तक सहजता से पहुंच जाए। अनेक देश हैं, जो सस्ते एआई मॉडल को बनाने और बेचने पर जोर देंगे। भारत भी खुद को इसी श्रेणी के देशों में रखना चाहेगा।

केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव भी इसी राह पर चलते दिख रहे हैं, तो आश्चर्य नहीं। उन्होंने हाल ही में भारत द्वारा स्वदेशी एआई मॉडल तैयार किए जाने की घोषणा की है। चीन आधारित एआई डीपसीक की भारी सफलता को देखकर भारत आत्मविश्वास के साथ अपने लार्ज लैंग्वेज मॉडल की कल्पना कर सकता है। हमें स्थानीय तौर पर विकसित ऐसे मॉडल की जरूरत है, जो यहां की भाषायी व सांस्कृतिक विविधता को समझ सके। खास तौर से यहां एआई को गैर-अंग्रेजीभाषी आबादी के अनुकूल बनाना होगा। ऐसे मॉडल को भारत के खास डेटासेट की कसौटी पर कसना होगा। ऐसी तमाम सूचनाओं का संयोजन करना होगा, जिसमें हमारी सांस्कृतिक व सामाजिक बारीकियों का पूरा ख्याल रखा जा सके। कोई भी विदेशी एआई भारतीयों की जिज्ञासा का समाधान नहीं कर पाएगा। यहां एक बड़ी चिंता आम भारतीयों की गोपनीयता और सुरक्षा की भी है। हमारी स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा संबंधी समस्याओं पर भी विशेष ध्यान देने की जरूरत है।

किफायती इंजीनियरिंग में अपनी विशेषज्ञता को देखते हुए हम एक ऐसा एआई मॉडल विकसित कर सकते हैं, जिसमें लागत काफी कम आए। मगर हमें इसे नागरिक-केंद्रित बनाना होगा, जो 1.4 अरब भारतीयों के लिए तैयार किया गया हो, ठीक डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना (डीपीआई) की तरह। जिस आसानी से भारतीय यूपीआई या डिजिटल पेमेंट सुविधा का लाभ ले रहे हैं, ठीक उसी तरह से भारत का अपना एआई भी होना चाहिए। निस्संदेह, इस राह में बहुत चुनौतियां हैं। यहां कई तरह के एआई मॉडल बनाने का अर्थ है कि हमें अधिक संसाधनों की जरूरत पड़ेगी। फिर, हमें प्रतिभा और अनुसंधान से जुड़ी चुनौतियां भी झेलनी होंगी। यही नहीं, ध्यान रखना होगा कि हम अब भी जीपीयू और चिप के लिए अमेरिका पर निर्भर हैं। मगर हमने पहले भी ऐसी सफलता हासिल की है, जैसे- सरकार, शिक्षाविदों और उद्योग जगत ने मिलकर डीपीआई तैयार किया, जिसने डिजिटल बदलाव को मुमकिन बनाया। साफ है, एआई अब राष्ट्रीय अभियान बन चुका है, ठीक डीपीआई या इसरो के अंतरिक्ष अभियानों या हरित क्रांति की तरह। भारत जब पहले इन तकनीकी क्षेत्रों में दुनिया को मात देने वाली मिसाल कायम कर चुका है, तो फिर एआई में क्यों नहीं? स्वदेशी एआई मॉडल एक अच्छी शुरुआत होगी। हमारे एआई से ज्यादा संवेदनशीलता और सजगता की उम्मीद रहेगी। यह कहना अभी जल्दबाजी होगी कि डीपसीक सच्चाई के पैमाने पर बहुत अच्छा है और इसके सभी दावे वैध हैं। यहां हमें सचेत रहना होगा और इसलिए भारतीय एआई का विकास अनिवार्य है। हमारे द्वारा विकसित एआई मानवता का भविष्य और इंटरनेट को व्यवस्थित करने का एक नया माध्यम हो सकता है। तकनीकी का महत्व बढ़ेगा, पर धीरे-धीरे नैतिकता तकनीक से ज्यादा महत्वपूर्ण होती जाएगी। केवल भारतीयों के लिए ही नहीं, इस ग्रह पर हम सभी आठ अरब लोगों के पास एआई-साक्षर होने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। आज जरूरी है कि तकनीक इंसानों को नियंत्रित न करे, बल्कि इंसान ही तकनीक का लाभ उठाते हुए विकास करे।

बता दें कि अमेरिका और चीन के बाद अब भारत भी खुद का जेनेरेटिव एआई मॉडल बनाने की तैयारी कर रहा है। इसमें 6-8 महीने का समय लग सकता है। इसका ऐलान केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ओडिशा में आयोजित उत्कर्ष कॉन्क्लेव में किया था। उन्होंने बताया था कि इंडिया एआई कंप्यूट फैसिलिटी के पास 18,693 जीपीयू हैं जिसकी मदद से एक लार्ज लैंग्वेज मॉडल (एलएलएम) तैयार किया जाएगा। यह खास तौर पर भारतीय लोगों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए डिजाइन किया जाएगा। वैष्णव ने कहा था कि हमारा मानना है कि ऐसे 6 बड़े डेवलपर्स हैं जो इस काम को 6-8 महीने में पूरा कर सकते हैं।

अगर चीजें बेहतर रहीं तो इसके 4-6 महीने में भी पूरा होने की उम्मीद हैं। उनका कहना है कि एक कॉमन कंप्यूट फैसिलिटी मजबूत एआई इकोसिस्टम बनाने के लिए बेहद जरूरी है। सरकार ने एआई कंप्यूट सेवाओं की कीमतों को बाजार दर से 42 प्रतिशत तक कम रखने की व्यवस्था की है, जिससे स्टार्टअप्स और शोधकर्ताओं को इसका अधिकतम लाभ मिल सके। हाई-प्रिसिजन कंप्यूट यूनिट्स, जो एआई मॉडल्स के लिए बेहद जरूरी हैं, उन्हें भी 47 प्रतिशत छूट के साथ उपलब्ध कराया जाएगा।

एआई कंप्यूट इन्फ्रास्ट्रक्चर के साथ-साथ, भारत सरकार अपना खुद का फाउंडेशनल एआई मॉडल भी विकसित कर रहा है। इस मॉडल को देश की भाषाई और सांस्कृतिक विविधता को ध्यान में रखते हुए डिजाइन किया जाएगा, जिससे डेटासेट्स में मौजूद कमियों को दूर किया जा सके। एआई टेक्नोलॉजी के सुरक्षित और जिम्मेदार उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए सरकार एक एआई सेफ्टी इंस्टीट्यूशन भी स्थापित करेगी। अन्य देशों के विपरीत, जहां अक रेगुलेटरी बॉडीज एक ही संस्थान के तहत काम करती हैं, भारत हब-एंड-स्पोक मॉडल अपनाएगा। इसके तहत कई संस्थान मिलकर सुरक्षा टूल्स और फ्रेमवर्क विकसित करेंगे।

विपक्ष को तो कोसा ही, चुनाव आयोग को भी नसीहत दे गए राजीव कुमार

देश के 25वें मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) राजीव कुमार रिटायर हो गए। उनकी जगह ज्ञानेश कुमार को भारत का मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है। राजीव कुमार ने अपने विदाई भाषण में कई महत्वपूर्ण बातें कहीं। उन्होंने इस ओर भी देश का ध्यान दिलाया कि कैसे हारने वाले दल अब बिना कोई सोच-विचार और प्रमाण के निर्वाचन आयोग पर उंगली उठा देते हैं। उन्होंने कहा कि चुनाव परिणाम इच्छा के अनुरूप नहीं आने पर चुनाव आयोग को बलि का बकरा बना दिया जाता है। यह सही नहीं है। उन्होंने चुनाव के समय और मतगणना के दौरान फैलने वाली झूठी खबरों और अफवाहों का भी जिक्र किया। नई दिल्ली स्थित भारत निर्वाचन आयोग में अपने विदाई भाषण में राजीव कुमार ने न्यायपालिका से भी एक अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि अदालती कार्यवाही में चुनाव की समय-सीमा का ध्यान रखा जाए। उन्होंने कुछ जरूरी चुनावी सुधारों की बात की। उन्होंने कहा कि चुनाव बाद मतदाताओं पर तरह-तरह के अत्याचार रोकने के लिए ईवीएम से वोटों की गिनती के वक्त टोटलाइजर मशीन के उपयोग और घरेलू प्रवासियों के साथ-साथ एनआरआई वोटरों को वोट देने में मदद करने के लिए तकनीकी समाधान जैसे उपाय होने चाहिए।

उन्होंने राजनीतिक दलों से अपील की कि वे मुफ्त उपहारों की घोषणाओं के साथ स्पष्ट वित्तीय जानकारी दें। राजनीतिक बहस के चिंताजनक स्वरूप पर भी विचार करें। कुमार सितंबर 2020 से चुनाव आयुक्त और मई 2022 से मुख्य चुनाव आयुक्त रहे। साढ़े चार साल के अपने कार्यकाल में उन्होंने एक पूरा चुनावी चक्र देखा। 31 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के विधानसभा चुनाव, 2022 के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनाव, 2024 के लोकसभा चुनाव और राज्यसभा के चुनाव। हालांकि, कुमार ऐसे समय में रिटायर हुए हैं जब विपक्षी दल चुनाव आयोग के कामकाज पर सवाल उठा रहे हैं। महाराष्ट्र में मतदाता सूची की स्थिति से लेकर मतदान केंद्रों की वीडियो रिकॉर्डिंग शेयर करने से रोकने के लिए नियमों में बदलाव, मतदान के आंकड़े और ईवीएम-वीवीपैट सत्यापन जैसे कई मुद्दों पर अदालती मामले चल रहे हैं। अपने विदाई भाषण में उन्होंने इन मुद्दों पर बात की। उन्होंने कहा कि चुनाव या मतगणना के दौरान भ्रामक बातें फैलाना जानबूझकर की गई कोशिश है। इसका मकसद तथ्यों को तोड़ना-मरोड़ना और मतदाताओं को गुमराह करना है। सभी उम्मीदवार और दल पूरी पारदर्शिता के साथ हर चरण में शामिल होते हैं। बिना किसी आपत्ति या अपील के हर कदम में भाग लेने के बावजूद बाद में संदेह पैदा करने की कोशिश करना ठीक नहीं है। बातचीत हमेशा सबसे अच्छा तरीका होना चाहिए। आयोग हमेशा सोच-समझकर और संयम से प्रतिक्रिया करता है। यह एक चिंताजनक चलन है और इसे जल्द ही बंद किया जाना चाहिए।

राजीव कुमार ने सोशल मीडिया कंपनियों से नकली सामग्री का पता लगाने और उसे चिह्नित करने का आग्रह किया। उन्होंने उन कई डिजिटल पोर्टल्स की ओर भी ध्यान दिलाया जो भ्रामक बातें और अर्धसत्य फैला रहे हैं। कुमार ने कहा कि चुनाव के दौरान और मतगणना के समय भ्रामक सूचनाएं फैलाई जाती हैं। यह तथ्यों को तोड़-मरोड़ कर पेश करने और मतदाताओं को गुमराह करने की एक सोची समझी रणनीति है। सभी उम्मीदवार और पार्टियां पूरी पारदर्शिता के साथ चुनाव प्रक्रिया के हर चरण में शामिल होती हैं। जब वे बिना किसी आपत्ति या अपील के हर कदम में हिस्सा लेते हैं, तो बाद में शक पैदा करना उचित नहीं है। बातचीत हमेशा सबसे अच्छा रास्ता होता है। आयोग हमेशा संयम और गंभीरता से काम लेता है, लेकिन यह एक चिंताजनक प्रवृत्ति है और इसे जल्द ही खत्म किया जाना चाहिए।

पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त एन. गोपालस्वामी ने 30 जून, 2006 से 30 अप्रैल, 2009 तक के अपने कार्यकाल में टोटलाइजर का नमूना तैयार कर राजनीतिक दलों को दिखाया था। उन्होंने पिछले वर्ष 2024 में इंटरव्यू में टोटलाइजर की भूमिका समझाई थी। उन्होंने बताया था कि ईवीएम के साथ पहले हर एक में दर्ज कुल वोटों की जांच की जाती है। ये आंकड़े पोलिंग स्टेशनों के पीठासीन अधिकारियों द्वारा दिए गए डेटा से मेल खानी चाहिए। एक और बटन दबाने पर ईवीएम में उम्मीदवार दर उम्मीदवार वोट दिखाई देते हैं। हालांकि, एक टोटलाइजर एक बार में 14 ईवीएम से जुड़ा होता है। ये 14 ईवीएम बेतरतीब ढंग से चुने जाते हैं - उदाहरण के लिए, पोलिंग स्टेशन 1, 40, 55, 31। और टोटलाइजर से उम्मीदवार दर उम्मीदवार जानकारी इन 14 ईवीएम के डेटा का कुल योग होती है। इसलिए, उम्मीदवार यह पता नहीं लगा सकते कि उन्हें किस इलाके में कितने वोट मिले। 2007 के यूपी चुनाव के बाद, हमने दो ईवीएम निमार्ताओं को एक टोटलाइजर बनाने के लिए कहा और यह लगभग चार महीनों में तैयार हो गया था। उसके बाद, हमारी टीम और तकनीकी टीम ने इसका परीक्षण किया। 2008 की शुरूआत में हमने राजनीतिक दलों को इसे देखने के लिए बुलाया। वे आए और कोई बड़ी आपत्ति नहीं जताई। उन सबने इसकी सराहना की लेकिन जैसा कि होता है, इस पद्धति को लागू करने के लिए आपको नियमों में संशोधन करने की आवश्यकता होती है। इसलिए, मामला संसदीय उपसमिति के पास गया, जिसने इसे मंजूरी नहीं दी। 2008 से 2024 तक 16 साल बीत चुके हैं लेकिन टोटलाइजर को अभी भी मंजूरी नहीं मिली है। 14 डिब्बों में अलग-अलग मिठाइयां हैं। टोटलाइजर एक बड़ा डिब्बा है जिसमें इन 14 डिब्बों की सभी मिठाइयां मिला दी जाती हैं। अब आपको यह पता नहीं चलेगा कि किस डिब्बे में कौन सी मिठाई थी।

इस सवाल पर पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त गोपालस्वामी ने एक घटना की याद की थी। उन्होंने कहा था कि 2007 के उत्तर प्रदेश चुनावों में कुछ ह्यबाहुबलियोंह्ण चुनाव लड़ रहे थे, खुद या अपने परिवार के सदस्यों और चमचों के जरिए। यह बात फैलाई गई थी कि जो बाहुबली के खिलाफ वोट देगा, उसे नतीजे भुगतने होंगे। हमने वोटर्स को भरोसा दिलाया कि पैरामिलिट्री फोर्सेस पोलिंग स्टेशन पर उनकी सुरक्षा करेंगी, लेकिन वो जानना चाहते थे कि बाद में उनकी देखभाल कौन करेगा। तभी हमें एहसास हुआ कि ईवीएम के जरिए पड़े वोटों को मिलाने के लिए हमें एक नए सिस्टम की जरूरत है।

संक्षेप में, चुनाव से पहले और बाद में परेशान किया जाना मुमकिन है। चुनाव आयोग चुनाव से पहले उत्पीड़न रोक सकता है, लेकिन बाद में नहीं। अगर जीतने वाले उम्मीदवार को पता चलता है कि किसी खास पोलिंग स्टेशन ने उन्हें वोट नहीं दिया, तो वो उस इलाके में कोई काम नहीं करवा सकते। मुझे एक उम्मीदवार का कहना याद है कि वे उस इलाके को काम से जीत लेंगे जिसने उन्हें वोट नहीं दिया। मुझे नहीं पता कि उनका मतलब यही था या यह टिप्पणी सिर्फ दिखावे के लिए था, लेकिन चुनाव के बाद उत्पीड़न का खतरा तो बना ही रहता है।

अब जानते हैं नए मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के बारे में। चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को भारत का मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में तीन सदस्यों वाली समिति की बैठक में सोमवार को यह फैसला किया गया। ज्ञानेश कुमार बुधवार यानी 19 फरवरी को मुख्य चुनाव आयुक्त की जिम्मेदार संभालेंगे। ज्ञानेश कुमार 1988 बैच के केरल कैडर के आईएएस अधिकारी हैं। 31 जनवरी, 2024 को ज्ञानेश कुमार यूनियन कोऑपरेशन सेक्रेटरी के पद से रिटायर हुए थे। केंद्रीय मंत्री अमित शाह के अंतर्गत आने वाले मंत्रालय में वे मई 2022 से सेक्रेटरी थे।

इसके दो महीने बाद 14 मार्च, 2024 को इन्हें चुनाव आयुक्त बनाया गया था। 15 मार्च को उन्होंने कार्यभार संभाला और उसके अगले दिन ही चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव के कार्यक्रम की घोषणा की थी। चुनाव आयुक्त का पद संभालने के लगभग एक साल बाद ही वे अब मुख्य चुनाव आयुक्त की जिम्मेदारी संभालने जा रहे हैं। उन्होंने इससे पहले पांच साल गृह मंत्रालय में काम किया था, जहां वह मई 2016 से लेकर सितंबर 2018 तक संयुक्त सचिव और उसके बाद सितंबर 2018 से लेकर अप्रैल 2021 तक अतिरिक्त सचिव के पद पर थे। अतिरिक्त सचिव के पद पर रहते समय ज्ञानेश कुमार जम्मू-कश्मीर के मामलों को देख रहे थे और अगस्त 2019 में अनुच्छेद 370 को रद्द करने की घोषणा की गई थी। एक रिपोर्ट के मुताबिक, अनुच्छेद 370 को रद्द करने का कानून जब लाया जा रहा था उस समय वह गृह मंत्री अमित शाह के साथ लगातार संसद में आते थे। एक रिपोर्ट के मुताबिक, नरेंद्र मोदी सरकार का ज्ञानेश कुमार में एक नौकरशाह के तौर पर भरोसा इस तथ्य से ही पता चलता है कि न केवल उन्हें गोपनीय विधेयकों में से एक जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन विधेयक को तैयार करने की जिम्मेदारी दी गई थी बल्कि वे राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के गठन में भी शामिल थे। इसी रिपोर्ट के मुताबिक, कोऑपरेशन सेक्रेटरी के उनके कार्यकाल के दौरान मल्टी-स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज (एमएससीएस) (संशोधन) विधेयक, 2023 पास किया गया था, जिसका लक्ष्य कोऑपरेटिव सेक्टर में पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ाना था। ज्ञानेश कुमार के चुनाव आयुक्त रहते हुए लोकसभा चुनाव 2024 हुए और साथ ही अनुच्छेद 370 की समाप्ति के बाद केंद्र शासित जम्मू-कश्मीर में पहली बार विधानसभा चुनाव हुए। इसके अलावा हरियाणा, झारखंड, महाराष्ट्र और दिल्ली में विधानसभा चुनाव हुए। मुख्य चुनाव आयुक्त के तौर पर ज्ञानेश कुमार का कार्यकाल 26 जनवरी 2029 तक होगा। उनके कार्यकाल में 20 विधानसभा चुनाव होंगे।

साथ ही 2027 में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव और 2029 लोकसभा चुनाव की तैयारी भी उन्हीं के कार्यकाल में होगी। ज्ञानेश कुमार ने आईआईटी कानपुर से सिविल इंजीनियरिंग में बीटेक किया है। उन्होंने इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड फाइनैंशियल एनालिस्ट्स ऑफ इंडिया से बिजनेस फाइनैंस में पढ़ाई भी की है।

जिलाधिकारी ने जनपद के व्यापारियों से योजना का लाभ उठाने हेतु की अपील

जीएसटी अधिनियम की धारा-73 के अंतर्गत सृजित की गई मांग के क्रम में अर्थदंड एवं ब्याज माफी योजना लागू

गौरव सिंघल । सिटी चीफ
सहारनपुर। जिलाधिकारी मनीष बंसल ने बताया कि भारत सरकार एवं उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 01.07.2017 से 31.03.2020 की अवधि में जीएसटी अधिनियम की धारा-73 के अंतर्गत सृजित की गई मांग के क्रम में अर्थदंड एवं ब्याज माफी योजना को लागू किया गया है जो कि 31 मार्च 2025 तक लागू है। इस योजना में संबंधित करदाता द्वारा सृजित मांग के संबंध में मूल कर की धनराशि को 31 मार्च 2025 तक जमा किए जाने तथा कोई अपील दाखिल न किए जाने अथवा दाखिल अपील वापस लिए जाने पर देय अर्थदंड एवं ब्याज पर पूरी छूट दी जा रही है। डीएम मनीष बंसल ने बताया कि जनपद में संबंधित में इस प्रकार कुल 4397 प्रकरण है जिसमें कर की धनराशि 44.43 करोड़ तथा अर्थदंड एवं ब्याज की धनराशि 59.5 करोड़ निहित है। उन्होंने कहा कि जनपद में संबंधित करदाताओं को इस योजना का लाभ उठाने हेतु उत्प्रेरित किया जाना आवश्यक है जिससे न केवल 59.5 करोड़ की अर्थदंड एवं ब्याज की माफी से संबंधित करदाताओं को बड़ी राहत मिलेगी अपितु जनपद में कुल 44.43 करोड़ की राजस्व की प्राप्ति भी 31 मार्च 2025 तक सुनिश्चित हो सकेगी।

एससीएसटी आयोग सदस्य ने सुनी जनसमस्याएं

आयोग सदस्य ने नगरपालिका सहित दलित बस्तियों,जाटव नगर,रविदास मार्ग का किया निरीक्षण

गौरव सिंघल । सिटी चीफ
सहारनपुर । देवबंद, एससीएसटी आयोग उत्तर प्रदेश सरकार के सदस्य महिपाल बाल्मिकी ने नगर में पहुंचकर दलित बस्तियों का भ्रमण करके उनकी समस्याओं को जाना। आयोग सदस्य महिपाल बाल्मिकी का जाटव नगर, रविदास मार्ग,राजकुमार जाटव पूर्व सभासद के निवास पर पगडी व शाल उढाकर भव्य स्वागत किया गया। कोरी समाज के लोगों ने भी आयोग सदस्य महिपाल बाल्मिकी का स्वागत किया। इसके बाद एससी एसटी आयोग के सदस्य महिपाल बाल्मिकी ने नगरपालिका में सफाई कर्मचारियों की समस्याओं को सुना। नगरपालिका के बाद आयोग सदस्य दलित बस्तियों रविदास मार्ग पहुंचे तथा यहां रहने वालों की समस्याओं को सुना। पूर्व सभासद राजकुमार जाटव ने आयोग सदस्य महिपाल बाल्मिकी को ज्ञापन देते हुए बताया कि जबसे फोरलेन सडक निर्माण हुआ है तब से सडक ऊंची उठाए जाने के कारण रविदास बस्ती गहराई में चली गई है। उन्होंने बताया कि प्रतिवर्ष वर्षा ऋतु में उनकी बस्ती में दो व तीन फीट पानी घरों में चला जाता है। जिससे लोगों का काफी नुकसान होता है और बच्चें स्कूल जाने से वंचित रह जाते है। आयोग के सदस्य ने उन्हें इस समस्या का समाधान कराने का आश्वासन दिया।इसके बाद आयोग सदस्य बाल्मीकि बस्ती पहुंचे तथा उनकी समस्याओं को सुना। बस्ती के लोगों ने अपनी समस्याएं बताई। इसके अलावा उन्होंने दलित बस्ती नया बास का भी भ्रमण करके वहां के लोगों की समस्याओं को सुना। सफाई कर्मचारियों ने आयोग अध्यक्ष को अपनी अनेक समस्याओं से अवगत कराया और आयोग सदस्य महीपाल बाल्मिकी ने सबको समस्या समाधान कराने का आश्वासन दिया। इस दौरान भाजपा नगर अध्यक्ष अरूण गुप्ता, यशपाल सिंह, प्रवीण कुमार जाटव, वेदप्रकाश जाटव, नितिन जाटव, अमरदीप प्ररोहित, मनोज कुमार जाटव, पोपिन कुमार स्वास्थ्य निरीक्षक, धीरेंद्र राय, अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद, पालेराम जाटव सहित बडी संख्या मे भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

जिला ओलंपिक संघ ने किया रिटा. मेजर जनरल दीप अहलावत का भव्य अभिनंदन

गौरव सिंघल । सिटी चीफ
सहारनपुर, उत्तर प्रदेश के प्रथम खेल विश्वविद्यालय मेजर ध्यान चन्द खेल विश्वविद्यालय के नवनियुक्त प्रथम कुलपति रिटा? मेजर जनरल दीप अहलावत, अर्जुन अवार्डी का सम्मान चिन्ह एवं शॉल भेंट कर जिला ओलंपिक संघ ने स्पोर्ट्स स्टेडियम में भव्य अभिनंदन किया।ओलम्पिक संघ के अध्यक्ष संजय गर्ग ने एक योग्य अंतर्राष्ट्रीय मेडल प्राप्त खिलाड़ी को उपकुलपति बनने हेतु मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए आभार प्रकट किया। समारोह का कुशल संचालन जिला जूडो संघ के सचिव दीपक गुप्ता ने किया। इस अवसर पर विशिष्ट अतिथि के रूप में मां शाकंभरी विश्वविद्यालय की प्रथम महिला कुलपति प्रोफेसर वाई. विमला, रिमाउंट डिपो के कमांडेंट कर्नल लवदीप यादव ने सम्मान समारोह की गरिमा बढ़ाई। वही कार्यक्रम की अध्यक्षता पूर्व मंत्री एवं मंडल ओलंपिक संघ के अध्यक्ष संजय गर्ग ने की।अतिथि गण का स्वागत, सम्मान मंडल ओलिंपिक संघ के सचिव डॉ ए के गुप्ता, जिला ओलिंपिक संघ के सचिव डॉ संदीप गुप्ता, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी चौधरी नीरपाल, अंतर्राष्ट्रीय जूडो रेफ़री दीपक गुप्ता, आरोग्य भारती के प्रान्त अध्यक्ष विनोद जैन, पंकज बंसल, रविंद्र शर्मा, अशोक सक्सेना, फुरकान अहमद, प्रो0 योगेश गुप्ता, सुधाकर अग्रवाल, विनोद माहेश्वरी, अमित चौधरी, संजय गुप्ता (प्रिंसिपल), सुनील गुप्ता, संजीव गुप्ता, लाल धर्मेंद्र, मुस्तकीम अंसारी, सरिता प्रजापति, रवि सिंघल, डॉ अतुल सिन्हा, क्षेत्रीय क्रीड़ाधिकारी, अश्वनी त्यागी, उप क्रीड़ाधिकारी डॉ रीता बोरा, रिदम गुप्ता, रविकांत धीमान, सोनवीर सिंह, आदेश कुमार, अरुणा जी, गौरव कपिल, सुषमा बजाज, अलंकार किशोर, मनीष कुमार आदि ने विभिन्न खेल संगठनों का प्रतिनिधित्व करते हुए माला, अंगवस्त्र एवं बुके देकर अतिथियों का अभिनन्दन किया।

डीएम ने मौके पर ही कराया लंबित पत्रावलियों का निस्तारण,चार घंटे के अंदर 26 लाभार्थियों को दिलाया 1.25 करोड़ से अधिक का ऋण

जिलाधिकारी की अध्यक्षता में हुई मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास योजना की समीक्षा बैठक

गौरव सिंघल । सिटी चीफ
सहारनपुर। जिलाधिकारी मनीष बंसल की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट स्थित नवीन सभागार में मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास योजना की समीक्षा बैठक सम्पन्न हुई। डीएम मनीष बंसल ने सभी बैंक प्रतिनिधियों को कड़े निर्देश देते हुए कहा कि योजना के क्रियान्वयन में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सभी बैंकों को निर्देशित किया कि इस महत्वकांक्षी योजना में फोकस करते हुए कार्य में तेजी लाएं। उन्होंने उपायुक्त उद्योग को निर्देशित किया कि बैंकवार अपनी टीम लगाकर उनकी समस्या का समाधान कराना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि जनपद के निर्धारित 2000 लक्ष्य के सापेक्ष अभी तक 1399 आवेदन हुए है, जिसे जल्द से जल्द बढ़ाते हुए पूर्ण किया जाए। डीएम मनीष बंसल ने योजना की समीक्षा करते हुए बैंक स्तर पर लंबित आवेदनों पर नाराजगी जताते हुए सभी बैंक प्रतिनिधियों को नवीन सभागार में बिठाकर मौके पर ही 04 घंटे के अंदर 80 से ज्यादा लॉन फाइलों की स्वीकृति कराते हुए 26 लाभार्थियों को 1.25 करोड़ से अधिक ऋण वितरित कराया गया। जिलाधिकारी मनीष बंसल ने बताया कि यह उत्तर प्रदेश सरकार की अति महत्वाकांक्षी योजना है जिसके अन्तर्गत सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों को गति प्रदान करते हुए इन उद्योगों को प्रोत्साहित करने एवं इस क्षेत्र में अधिक से अधिक रोजगार सृजित किये जाने तथा प्रदेश में पूंजी निवेश को आकर्षित करने हेतु प्रतिवर्ष 01 लाख नई सूक्ष्म इकाईयां स्थापित किये जाने के लक्ष्य निर्धारित किया गया है। जिसके क्रम में जनपद को 2000 ऋण वितरण किए जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इस योजना में 5 लाख रूपये तक ऋण जिला उद्योग केंद्र के माध्यम से बैंको द्वारा वितरित किए जायेंगे। योजना में मुख्य रूप से 10 प्रतिशत सब्सिडी दी जाएगी जो ब्याज मुक्त योजना है।बैठक में उपायुक्त उद्योग वीके कौशल, लीड बैंक मैनेजर प्रवीण जमुआर सहित संबंधित अधिकारी एवं विभिन्न बैंको के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।

सत्य काम फाउंडेशन के खिलाफ कर्मचारियों का धरना

एसपी कार्यालय के बाहर प्रदर्शन

सुनील यादव । सिटी चीफ
कटनी, कटनी जिले एसपी कार्यालय के सामने समूह लोन देने वाली कंपनी सत्य काम फाउंडेशन के कर्मियों ने धरना दे दिया, सत्य काम फाउंडेशन का कार्यालय जो एन के जे थाना क्षेत्र स्थित है धरने पर बैठे कर्मचारियों का आरोप है कि वे लोग सभी मध्यप्रदेश के अलग-अलग जिले के लोग है, सत्य काम फाउंडेश के अधिकारियों ने उन्हें नौकरी का प्रलोभन दे उनसे सुरक्षा निधि के नाम से करोड़ों रुपए ले लिए है और कुछ माह काम करने बाद जब उनका वेतन भी नहीं दिया गया तो वे सभी कंपनी के अधिकारियों से अपना पैसा मंगा तो उन्होंने पैसा देने से मना कर दिया जिसके चलते वे लोग आज एसपी कार्यालय पहुंच कंपनी के संचालक के खिलाफ मामला दर्ज करने पहुंचे है। सत्य काम फाउंडेशन कंपनी के कर्मचारियों ने बताया वेंकॉग मध्यप्रदेश के अलग अलग जिले के लोग है इस कंपनी की मेन ब्रांच बिहार में है और कटनी जिले निवासी के दो अधिकारी अखिलेश कुमार केवट और अजय कुमार है जो जिले के ही निवासी है और उन्होंने ने इस कंपनी का कार्यालय एन के जे थाना क्षेत्र पाठक कॉलोनी में बनाया था और उन्होंने कंपनी में नौकरी देने के लिए विज्ञापन निकाला था और जब वह नौकरी के लिए इस कंपनी के अधिकारियों के पास पहुंचे थे उन्होंने पहले उनसे सुरक्षा निधि के नाम से अलग अलग पोस्ट के आधार पर 50 से 75 हजार रुपए ले लिए इस कंपनी में मध्यप्रदेश में हजारों लोग ने काम किया है लेकिन उनकी आज दिनांक तक उनका वेतन नहीं दिया गया और जब भी इससे अपनी सुरक्षा निधि मांगी जाती है तो वे लोग साफ माना कर रहे है जिसकी रिपोर्ट लिखने एन के जे थाने में पहुंचे थे लेकिन उनकी रिपोर्ट नहीं लिखी गई जिससे आकृषित 60 से 70 कर्मचारी एसपी कार्यालय पहुंच कंपनी के अधिकारी और इसके संचालक के खिलाफ द्धद्धह्म दर्ज कराने पहुंचे है और जब तक द्धद्धह्म नहीं होती है तब तक वे लोग धरने पर बैठे रहेंगे। वही एडिशन एसपी संतोष डेहरिया ने बताया कि इन सभी कर्मचारियों की शिकायत ले पूरे मामले की जांच कराई जा रही है और इस मामले में जो दोषी होगा कार्यवाही की जाएगी।

दोपहिया वाहन चालक एवं सहयात्री का हेलमेट पहनना अनिवार्य - जिलाधिकारी मनीष बंसल

जिलाधिकारी ने यात्रा के दौरान हेलमेट एवं सीट बेल्ट लगाने के लिए जारी किया आदेश

गौरव सिंघल। सिटी चीफ
सहारनपुर। जिलाधिकारी मनीष बंसल ने निर्देश दिए कि जनपद के सभी शासकीय एवं अर्द्ध-शासकीय कार्यालयों के अधिकारी एवं कर्मचारी जो दोपहिया वाहन से कार्यालय आते हैं, वे हेलमेट अनिवार्य रूप से पहनें और उनके साथ यात्रा करने वाले सहयात्री के लिये भी हेलमेट पहनना आवश्यक है। डीएम मनीष बंसल ने निर्देश दिए कि इसी प्रकार जो अधिकारी एवं कर्मचारी चारपहिया वाहन से कार्यालय आते हैं वे वाहन चलाते समय मोबाइल का प्रयोग न करें एवं अन्य सभी सह यात्रियों के लिये सीट बेल्ट पहनना अनिवार्य है। उन्होंने निर्देश दिए कि सभी कार्यालयाध्यक्ष एवं विभागाध्यक्ष यह सुनिश्चित करें कि उनके अधीनस्थ अधिकारी एवं कर्मचारियों निर्देशों का कड़ाई से पूर्णत: पालन करें। जिलाधिकारी मनीष बंसल ने निर्देश दिए कि सभी शासकीय एवं अर्द्धशासकीय कार्यालयों के प्रवेश द्वार पर सुरक्षाकर्मी हेलमेट एवं सीट बेल्ट की जांच करें, बिना हेलमेट एवं सीट बेल्ट के प्रवेश करने पर रोक लगायी जाए। यातायात पुलिस और जिला प्रशासन इस नियम का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित करें और उल्लंघन करने वालों पर आवश्यक कार्यवाही करे। सभी कर्मचारी सड़क सुरक्षा को बढावा देने हेतु जागरूक हो और हेलमेट व सीट बेल्ट के उपयोग को अपनी दिनचर्या का अनिवार्य हिस्सा बनाएं। नियमों का उल्लंघन करने वाले अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही पर विचार किया जाए।

विधायक की अनुशंसा पर जाम संकुल यथावत रहेगा

लाकेश पंचेश्वर । सिटी चीफ
लालबर्रा, लालबर्रा जनपद पंचायत क्षेत्र अंतर्गत शिक्षा विभाग के जाम को यथावत संकुल केंद्र रखा गया हैं। विधायक अनुभा मुंजारे की अनुशंसा पर जाम को संकुल केंद्र के रूप में शासन की ओर से यथावत रखे जाने के निर्देश दिये गये हैं। उल्लेखनीय हैं कि शासन स्तर पर इस क्षेत्र के 7 संकुल केंद्रों में से 2 को हटाया जा रहा था और उन्हें अन्य शेष 5 केंद्रों में मिलाया जाने वाला था। जिसमें जाम संकुल केंद्र भी शामिल था और यह संकुल अब नहीं रहने वाला था। जिसके संबंध में ग्रामीणों सहित जाम संकुल के शिक्षकों व स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने विधायक अनुभा मुंजारे का ध्यानाकर्षित कराते हुये जाम को संकुल केंद्र यथावत रखे जाने की मांग की थी। विधायक ने इस संज्ञान में लाये गये मामले को गंभीरता से लेते हुये शासन व प्रशासन स्तर पर पत्राचार किया और अब जाम संकुल को यथावत रखे जाने के निर्देश जारी किये गये हैं। विधायक अनुभा मुंजारे के प्रयास से अब जाम संकुल बंद नहीं होगा बल्कि यथावत रहेगा और इस संकुल के अंतर्गत सभी स्कूलें यथावत इसी संकुल में समाहित रहेगी। विधायक अनुभा मुंजारे ने कहा कि जाम संकुल को समाप्त कर इस संकुल के स्कूलों को दूसरे अन्य संकुल में शामिल करने की जानकारी उन्हें प्राप्त हुई थी। साथ ही जाम संकुल को यथावत रखे जाने के लिये मांग की गई थी। इस मांग को गंभीरता से लेते हुये प्रयास किये गये। उच्च स्तर पर इस संबंध में चर्चा की गई और उन्होने अब जाम को संकुल केंद्र के रूप में यथावत रखे जाने की अनुशंसा की हैं। जाम संकुल यथावत रहेगा। श्रीमती मुंजारे ने कहा कि क्षेत्र की किसी भी समस्या या कार्य को लेकर कही कोई दिक्कतें हैं तो उसके निराकरण हेतु वह लगातार कार्य कर रही हैं। इसी के तहत उन्होने जाम संकुल को लेकर किया हैं। शिक्षा विभाग में जहां भी ऐसी कोई असुविधा की जानकारी सामने आयेगी तो वे उसके लिये बच्चों व शिक्षा के हित में कार्य किया जायेगा। जाम संकुल यथावत रखे जाने की जानकारी सामने आने पर क्षेत्र के लोगों ने हर्ष जताते हुये विधायक अनुभा मुंजारे के प्रति आभार जताया हैं।

विधुत विभाग की बड़ी कार्यवाही

दर्जन भर घरों में चोरी की बिजली से बनाया जा रहा था खाना मौके पर हीटर जप्त

धीरज कुमार अहीरवाल । सिटी चीफ
दमोह, विद्युत विभाग द्वारा दमोह दक्षिण संभाग अंतर्गत आने वाले ग्रामीण वितरण केंद्र के ग्रामों में बिजली चोरी रोकने के लिए सघन चेकिंग अभियान चलाया गया। कार्यपालन अभियंता श्री एम.एल. साहू के निर्देशन में कनिष्ठ अभियंता कु. सरिता रावत के नेतृत्व में टीम तैयार कर ग्रामीण वितरण केन्द्र अंतर्गत आने वाले ग्राम ग्वारी, हिनौती, अथाई, बरपटी आदि क्षेत्रों में छापामार कार्यवाही की गई। इस दौरान अनेक घरों में अवैध रूप से बिजली की चोरी कर हीटर के द्वारा खाना पकाया जा रहा है। विधुत विभाग की टीम द्वारा मौके से एक दर्जन से अधिक घरों में चोरी की बिजली से चलने वाले हीटरों को जप्त करते हुए पंचनामा बनाकर प्रकरण तैयार किया गया। इस दौरान कई उपभोक्ताओं द्वारा अपने घरों से हीटरों को हटाने में लग गये। कनिष्ठ अभियंता कु. सरिता यादव द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया कि इन सभी ग्रामों से अनावश्यक लोड बढ़ने , केबिल जलने , ट्रांसफार्मर खराब होने तथा डी.ओ. गिरने आदि की शिकायतों में एकाएक वृद्धि होने से कार्यपालन अभियंता के निर्देशन में विशेष टीम तैयार कर इन ग्रामों में चैकिंग कराई गई। हकीकत जानने के लिये जब मौके पर जाकर मुआयना किया गया तो बिजली चोरी सामने आई। जिन घरों में बिजली चोरी पाई गई वहां विधुत चोरी की धारा 135 के तहत प्रकरण बनाकर जप्ती की कार्यवाही की गई। इस प्रकार की चैकिंग कार्यवाही सतत् जारी रहेगी।
चेकिंग के दौरान कनिश्ठ अभियंता कु. सरिता रावत, प्रदीप बैश्णव, श्याम पटैल, रामलखन कुशवाहा , रोशन चौरसिया, आदि मौजूद रहे।

नोहटा के कलचुरी कालीन मंदिर को प्रदेश, देश और दुनिया के पटल पर लाने का छोटा सा प्रयास है, जिसमें आप सभी का सहयोग अपेक्षित-राज्यमंत्री धर्मेन्द्र सिंह लोधी

बैठक में सामाजिक संगठनों एवं मीडियाजनों से हुई चर्चा

धीरज कुमार अहीरवाल । सिटी चीफ
दमोह, नोहलेश्वर महोत्सव सांस्कृतिक चेतना यात्रा 19 फरवरी को दोपहर 2 बजे दमोह के जटाशंकर से शुरू कर रहे हैं जिसमें बुंदेलखंड की परम्परायें, बुंदेलखंड के नृत्य इन सभी का प्रदर्शन यात्रा में होगा। बुंदेलखंड की संस्कृति आगे बड़े इस उद्देश्य से सांस्कृतिक चेतना यात्रा निकाल रहे हैं। इसमें सभी सामाजिक संगठन के लोग शामिल होंगे, यात्रा जटाशंकर धाम से कीर्ति स्तंभ, घंटाघर, राय तिराहा, स्टेशन चौक, तीन गुल्ली, कॉलेज रोड, किल्लाई नाका, नव जागृति स्कूल, महाराणा प्रताप चौक और कृष्णा पैलेस यहां तक पैदल यात्रा रहेगी जिसमें सभी संगठन रहेंगे। इस आशय की बात प्रदेश के संस्कृति, पर्यटन, धार्मिक, न्यास एवं धर्मस्व राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) धर्मेन्द्र सिंह लोधी ने आज कलेक्टर कार्यालय के सभाकक्ष में आयोजित विभिन्न सामाजिक और स्वयं सेवी संगठनों और मीडिया से चर्चा करते हुये कही। संस्कृति राज्यमंत्री ने कहा 19 फरवरी से पूरे दस दिवसीय मेले का कार्यक्रम और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे, इसमें बड़े-बड़े कलाकार शामिल होंगे। उन्होंने कहा निश्चित रूप

से ऐतिहासिक कार्यक्रम नोहटा में होने जा रहा है, इसके साथ-साथ हेलीकॉप्टर राईड की सुविधा भी दी जाएगी, जो लोग हेलीकॉप्टर राइड का आनंद लेना चाहते हैं इसकी सुविधा शासन मेले में उपलब्ध कराई जा रही है, निश्चित रूप से बहुत ही दिव्य और भव्य कार्यक्रम होने जा रहा है। सभी से आग्रह है कि अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित होकर इस महोत्सव को सफल बनाएं। राज्यमंत्री ने कहा बहुत समय से लोगों की मांग थी कि नोहलेश्वर महोत्सव शुरू होना चाहिए, नोहलेश्वर महोत्सव के नाम से यह महोत्सव शुरू किया जा रहा हैं, महोत्सव के साथ-साथ प्रदेश स्तरीय मेला भी लगाया जाएगा। यह छोटा सा प्रयास है, इस प्रयास के द्वारा नोहटा के कलचुरी कालीन मंदिर को प्रदेश, देश और दुनिया के पटल पर लाने का छोटा सा प्रयास है, जिसमें आप सभी का सहयोग अपेक्षित है। महोत्सव में एक अच्छा कवि सम्मेलन आयोजित होने जा रहा है। 20 फरवरी को जबलपुर के विनोद कुमार द्वारा आल्हा भक्ति गायन का कार्यक्रम होगा, साथ में स्थानीय प्रस्तुतियां भी आयोजित की जाएगी। उन्होंने कहा बड़े कलाकारो के प्रोग्राम के साथ ही जो स्थानीय कलाकार है जिन्हें मंच नहीं मिलता है प्रयास किया गया है कि उनको भी मंच दिया जाये, हर दिन स्थानिक कार्यक्रम होंगे और उसके बाद प्रमुख कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। मेले में हेलीकॉप्टर राइड की सुविधा कंफर्म हो गई है, हेलीकॉप्टर को 6 सीटर किया गया है, यह पहला प्रयास है जिसमें 500 से 600 बुकिंग हो चुकी है एक दिन में 200 लोगों की ही यात्रा कराई जाएगी, 5 दिन में लगभग 1000 लोगों को यात्रा कराई जाएगी, यात्रा 10 मिनट कराई जाएगी। 19 फरवरी को किशनगंज के जितेंद्र खरे द्वारा बुंदेली राई नृत्य का कार्यक्रम होगा। नोहटा महोत्सव कार्यक्रम को संस्कृति विभाग के कैलेंडर में भी शामिल किया गया है, यह महोत्सव निरंतर होता रहेगा। राज्यमंत्री ने बताया 18 से 28 फरवरी तक दिव्य और भव्य मेला भी लगाया जाएगा। महोत्सव में सांस्कृतिक कार्यक्रम 18 से 28 फरवरी तक चलेंगे, जिसमें स्थानीय कलाकारों, बुंदेलखंड के कलाकारों को अवसर दिया जाएगा, इसके साथ-साथ 22 से 26 फरवरी तक संस्कृति विभाग के द्वारा विशेष कार्यक्रम आयोजित होंगे, जिसमें गायिका शहनाज अख्तर भी आयेंगी, आदिवासी नृत्य गुदुंब बाजा स्थानीय कलाकारों द्वारा 22 फरवरी को प्रस्तुतियां होंगी, 23 फरवरी को कुनाल गांजा वाला गायक एवं भरतनाट्यम, शास्त्रीय नृत्य, राजस्थानी लोक नृत्य राजस्थानी कलाकारों एवं स्थानीय कलाकारों द्वारा प्रस्तुतियां होंगी, 24 फरवरी को प्रसिद्ध गायिका पलक मुछाल उपस्थित होंगी और अपने गायन के द्वारा सभी का मन मोह लेने का काम करेंगी, कथकली, कुचिपुड़ी, शास्त्रीय नृत्य एवं स्थानीय कलाकार द्वारा भी प्रस्तुतियां होंगी, 25 फरवरी को पंचनाथ जुगलबंदी, कवि सम्मेलन जिसमें शैलेश लोढ़ा, भवन मोहिनी, लक्ष्मण नेपाली सहित अन्य कवियों के साथ एक कवि सम्मेलन संपन्न होगा और स्थानीय कलाकारों द्वारा उस दिन प्रस्तुतियां दी जायेंगी, 26 फरवरी को प्रसिद्ध गायिका अभीलिप्सा पांडा, लखबीर सिंह लक्खा हमारे बीच होंगे, इनके साथ-साथ स्थानीय प्रस्तुतियां भी होगी। इस प्रकार 10 दिन के कार्यक्रम 28 फरवरी तक हैं, जिसमें हर दिन सांस्कृतिक प्रस्तुतियां होगी। 22 फरवरी से 26 फरवरी तक संस्कृति विभाग के द्वारा विशेष सांस्कृतिक प्रस्तुतियां होंगी। कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर ने कहा मंत्री जी के मार्गदर्शन में नोहटा मंदिर और उसके आसपास के क्षेत्र का निरीक्षण कर लिया था, वहां की तैयारी को एक बार देख लिया है कि कितनी संख्या में लोगों के आने का अनुमान है, इस हिसाब से सारी व्यवस्थाएं एक दम चाक चौबंद की जाएगी। इस आयोजित बैठक में नोहलेश्वर महोत्सव चेतना यात्रा के उपलक्ष्य में आयोजित मीटिंग में आज दमोह नगर के विभिन्न सामाजिक संगठन /व्यापारिक संगठन /धार्मिक संगठनो सहित स्वयंसेवी संगठनों के लोगों द्वारा सहभागिता की गई। प्रमुख रूप से उपस्थित संगठन, संत निरंकारी सत्संग मंडल,विश्व हिंदू परिषद, गायत्री परिवार, गुरुद्वारा प्रबंध कमेटी, मुस्लिम समाज, लघु उद्योग भारती, वैश्य समाज, लायंस क्लब रोटरी क्लब, हिंदी लेखक संघ, यादव महासभा जैन मिलन, एनजीओ प्रकोष्ठ, किसान मोर्चा, क्षत्रिय कुर्मी समाज सहित विभिन्न स्वयंसेवी संगठनों के पदाधिकारियों द्वारा सहभागिता की गई। ज्ञात हो कि आज कलेक्टर कार्यालय सभाकक्ष में प्रारंभ में बैठक आयोजित हुई, उसके बाद मीडिया के साथ वार्ता संपन्न हुई।

जिपं. सीईओ ने जनसुनवाई में सुनी आवेदकों की समस्याएं अधिकारियों को आवेदनों का निराकरण करने के दिए निर्देश

जनसुनवाई में 72 आवेदन हुए प्राप्त

सुशिल सोनी । सिटी चीफ
अनूपपुर, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री तन्मय वशिष्ठ शर्मा ने मंगलवार को जनसुनवाई में जिले के नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों से आए आवेदकों की समस्याएं सुनी। जनसुनवाई में 72 आवेदन प्राप्त हुए। जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने जनसुनवाई में आए हर एक आवेदक की समस्याओं को धैर्यतापूर्वक सुना और उन्हें आवेदन के शीघ्र निराकरण का आश्वासन भी दिया। उन्होंने मौके पर मौजूद अधिकारियों को नागरिकों से प्राप्त आवेदनों पर संवेदनशील रुख अपनाते हुए निराकरण करने के निर्देश दिए। उन्होंने आवेदकों की समस्याओं पर संबंधित क्षेत्र के अधिकारियों को कार्यवाही करने के निर्देश दिए। जनसुनवाई में अपर कलेक्टर श्री दिलीप पाण्डेय सहित विभिन्न विभागों के जिला अधिकारीगणों ने भी आवेदकों की समस्याएं सुनी।

जनसुनवाई में तहसील जैतहरी के ग्राम लहरपुर निवासी श्री धनराज भैना ने पीएम आवास योजना का लाभ दिलाए जाने, तहसील जैतहरी के ग्राम सिवनी निवासी श्री भगवानदीन राठौर ने पेड़ों की अवैध रूप से कटाई व बिक्री की जांच एवं कार्यवाही के संबंध में, तहसील जैतहरी के ग्राम लहसुना निवासी श्री उपेन्द्र सिंह ने विद्युत कनेक्शन कराए जाने के संबंध में, अनूपपुर निवासी जलेबिया बाई कोल ने संबल कार्ड के तहत सहायता राशि प्रदान करने, नगर परिषद बिजुरी के वार्ड क्रमांक 7 निवासी श्री शिव प्रसाद बसोर ने धारणाधिकार योजना का लाभ दिलाए जाने, वार्ड नंबर 13 जैतहरी निवासी बेलाबाई चौधरी ने दुकान जल जाने के कारण आर्थिक सहायता राशि प्रदान करने के संबंध में आवेदन प्रस्तुत किए।

कुपोषित बच्चों को उचित पोषण एवं स्वास्थ्य सुविधा मिले- कलेक्टर

शहरी क्षेत्र की आंगनबाड़ियों का लिया जायजा नाश्ता, भोजन चखकर देखा

धीरज कुमार अहीरवाल । सिटी चीफ
दमोह, कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर ने आज दमोह शहरी क्षेत्र के आंगनबाड़ी केंद्रों का प्रातः 10 से सिविल वार्ड नं.-1 केंद्र क्रमांक 82, राजेंद्र प्रसाद वार्ड 35 आंगनबाड़ी केंद्र क्रमांक 97, गुरु गोविंद सिंह वार्ड 26 केंद्र क्रमांक 46 में संचालित आंगनबाड़ी केन्द्रों का निरीक्षण किया । कलेक्टर ने आंगनबाड़ी केंद्रों के निरीक्षण में कार्यकर्ताओं द्वारा लिए जा रहे शारीरिक माप वजन की गुणवत्ता और सटीकता की जांच का जायजा लिया। आंगनबाड़ी केंद्र क्रमांक 82 सिविल वार्ड-1 में निरीक्षण के दौरान कलेक्टर ने स्व सहायता समूह द्वारा वितरित नाश्ता एवं भोजन की गुणवत्ता नियम अनुसार समय से वितरण की जानकारी भी वार्डवासियो से ली एवं स्वयं नाश्ता भोजन चखकर भी देखा।
कलेक्टर ने आंगनबाड़ी केन्द्रों पर संधारित होने वाली विभिन्न पंजियों, टीकाकरण पंजी, वजन रजिस्टर आदि का अवलोकन किया एवं प्रविष्ट जानकारी का स्वयं समक्ष में वजन एवं ऊंचाई माप कर सत्यापन भी किया । साथ ही पोषण ट्रैकर एप में की गई प्रविष्टियां से भी मिलान किया।

कलेक्टर द्वारा सभी आंगनबाड़ी केन्द्रों में आयोजित होने वाले शारीरिक माप दिवसों की सघन निगरानी की जा रही है। शारीरिक माप दिवसों का एक अभियान के रूप में सभी केन्द्रों में आयोजन किया जा रहा है, जिसका मुख्य उद्देश्य कुपोषित एवं मध्यम कुपोषित बच्चों का चिन्हांकन कर उन्हें उचित पोषण एवं स्वास्थ्य सुविधा प्रदाय करना है। सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को शारीरिक माप दिवसों में सटीक वास्तविक गुणवत्तापूर्ण ऊंचाई/लंबाई एवं वजन लिए जाने हेतु निर्देशित किया गया है, जिसका व्यवस्थित अभिलेख संधारण एवं पोषण ट्रैकर एप में प्रविष्टि किया जाना समय सीमा में सुनिश्चित करना है।
आंगनबाड़ी केंद्र क्रमांक 97 राजेंद्र प्रसाद वार्ड 35 में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता गायत्री चौरसिया द्वारा आंगनबाड़ी केंद्र का नियमित संचालन एवं पंजीयों के व्यवस्थित संधारण एवं पोषण ट्रैकर एप में सटीक एवं गुणवत्तापूर्ण प्रविष्टि करने के लिए प्रशंसा की गई एवं आंगनबाड़ी केंन्द्र को विभागीय आंगनबाड़ी भवन में स्थानांतरित करने हेतु निर्देशित किया गया। कुपोषित बच्चों को उचित पोषण एवं स्वास्थ्य सुविधा मिले इस हेतु निर्देशित किया गया।
आंगनबाड़ी केंद्र क्रमांक 46 गुरु गोविंद सिंह वार्ड 26 में टीकाकरण सत्र का निरीक्षण किया गया, जिसमें उपस्थित एएनएम मोहिनी ठाकुर द्वारा समक्ष में गर्भवती महिलाओं की एएनसी चेकअप, हीमोग्लोबिन जांच, शुगर जांच, ब्लड प्रेशर माप करवाया गया। साथ ही बच्चों के टीकाकरण, ड्यू लिस्ट, टीकाकरण के बाद चार संदेश आदि की जानकारी भी ली गई।

थाना रामनगर द्वारा जुआ फड एवं पास से नगदी 3,130 रूपये जप्त कर 04 जुआडियो के विरूद्ध की गई कार्यवाही

सुशिल सोनी । सिटी चीफ
अनूपपुर, श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय अनूपपुर द्वारा विगत दिनों अवैध गतिविधियों जुआ सट्टा पर प्रभावी कार्यवाही हेतु आदेशित किया गया है कि जिस पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन एवं एसडीओपी महोदय कोतमा के मार्गदर्शन में थाना रामनगर के द्वारा दिनांक 18.02.25 को मुखबिर की सूचना पर क्रिकेट ग्राऊण्ड के पास टांकी रोड़ मलगा में आरोपीगण 01- बिसाहूलाल केवट पिता रामदीन केवट उम्र 38 वर्ष निवासी ग्राम वार्ड के0 20 मलगा, 02. जमुना प्रसाद केवट पिता हंसराम केवट उम्र 34 वर्ष निवासी वार्ड कं0 16 मलगा, 03. किशन केवट पिता लखन लाल केवट उम्र 24 वर्ष निवासी वार्ड

कं0 18 मलगा, 4. राजेन्द्र प्रजापति पिता हीरालाल प्रजापति उम्र 36 वर्ष निवासी वार्ड क्रे0 09 मलगा थाना रामनगर को जुआ खेलते पाये जाने पर तास के 52 पत्ते, नगदी 3,130 रूपये जप्त किया गया व आरोपीगणो के विरूद्ध थाना रामनगर में अपराध क0 41/25 धारा 13 जुआ एक्ट की कार्यवाही की गई। उक्त थाना प्रभारी रामनगर उपनिरी सुमित कौशिक के नेतृत्व में प्रआर0 84 सनत द्विवेदी, प्रआर0 11 हरीमा डेहरिया, प्रआर0 89 अमित पटेल, आर0 389 मनौज उपाध्याय, आर0 464 विनोद मरावी का सराहनीय योगदान है।

कोतमा पुलिस द्वारा तीन चोरी के आरोपियो को किया गिरफ्तार

सुशिल सोनी । सिटी चीफ
अनूपपुर, फरियादी असीम अती पिता मुख्तार अती उम्र 38 वर्ष ग्राम पकरिहा श्रमिक नगर थाना कोतमा जिला अनूपपुर का दि. 17.02.2025 को रिपोर्ट किया कि सेमरिहा चौराहा के पास मनसुख लाल अगरिया के किराये के मकान में अती पोल्ट्री ट्रेडर्स के नाम से दुकान संचालित है उक्त दुकान में दिनांक 16ड्ड17/02/25 की दरम्यानी रात्रि को पीछे दीवाल में सेंधमारी कर करीबन 8000 रुपये दुकान बिक्री रकम को लोहे के बक्से में रखा था बक्से से चोरी कर भाग गए संदेह है की शीतल अगरिया अपने साथियो के साथ चोरी किया हो रिपोर्ट पर अपराध क्र. 61/2025 धारा 331(4),305 (ए) बी.एन.एस कायम कर विवेचना में लिया गया विवेचना दौरान संदेही शीतल अगरिया को अभिरक्षा में लेकर पूछताछ करने पर शीतल अगरिया पिठा लल्लू अगरिया 19 वर्ष, सुन्दर यादव उर्फ टिक्कू यादव पिता रामविशाल यादव 27 वर्ष, अजीत पाव पिता लखन पाठ उम्र 22 वर्ष सभी निवासी रजबांध थाना बुढार जिला शहडोल के साथ मुर्गा पार्टी करने के लिए पैसा चोरी करना छीनी हथौड़ी से दुकान के पीछे की दीवाल तोड़कर गत्ता लाकर से पैसा चोरी करना बताने पर तीनो आरोपियो को दस्तयाब कर घटना में प्रयुक्त आलाजरब छीनी हथौडी, चोरी के 2000 रूपये आरोपी उपरोक्त से जप्त कर आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड पर न्यायालय पेश किया गया है।
उपरोक्त कार्यवाही में थाना प्रभारी सुन्द्रेश सिंह, स.उ.नि. बृजेश कुमार पाण्डेय, प्र.आर. कपिल उइके, आर. सत्यभान, मुमताज खान की सराहनीय भूमिका रही है।

कहां खो गए अनूपपुर जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर आर के वर्मा

झोला छाप डॉक्टरों के ऊपर आखिर कब होगी कार्रवाई

सुशिल सोनी । सिटी चीफ
अनूपपुर, जिले में इन दिनों गली-गली गांव-गांव शहर शहर में झोला छाप डॉक्टर क्लीनिक डाले बैठे हैं जिनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है जिले के अधिकारी ऐसा लगता है उनकी आंखों में पट्टी बंधी हुई है और हाल ही में एक व्यक्ति की जान जा चुकी है झोलाछाप डॉक्टर जो अपने आप को बहुत बड़ा डॉक्टर बताते हैं और गरीबों का खून चूसते हैं अनाप-शनाप पैसा लेते हैं 200 से 300 उनकी फीस होती है ऐसे में कोई व्यक्ति को अगर कुछ हो जाता है तो शासन के आला अधिकारी को अगर हम जानकारी देते हैं तो वह बोलते हैं की टीम गठित हो रही है हम जल्दी कार्रवाई करेंगे आज हम 2 महीने से बोलते जा रहे हैं पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है जिसके कारण कोतमा के एक फॉरेस्ट गार्ड की मौत हो गई उसके बाद भी इन अधिकारियों को ध्यान नहीं आ रहा है ऐसा लगता है डॉ आर के वर्मा टीम 2 महीने से तैयार कर रहे हैं आखिर डॉक्टर आरके वर्मा क्यों नहीं टीम तैयार कर पा रहे हैं किन अधिकारियों के कारण वह टीम गठित नहीं कर पा रहे हैं ऐसे अधिकारियों के ऊपर जिला प्रशासन से अनुरोध है की जल्द से जल्द ऐसे झोला छाप डॉक्टरों के ऊपर और उन अधिकारियों के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए अतः किसी गरीब की झोलाछाप डॉक्टर जान ले सकते हैं।।

नर्मदा महोत्सव की सफलता में मीडिया की भूमिका

पत्रकार सुशील सोनी हुए सम्मानित

सुशील सोनी । सिटी चीफ
अनूपपुर, अनूपपुर जिले में स्थित अमरकंटक नर्मदा उद्गम स्थल पर जनसंपर्क अनूपपुर एवं कलेक्टर के द्वारा नर्मदा महोत्सव मनाया गया जिसमें पत्रकारों द्वारा नर्मदा महोत्सव का एक सार्थक एवं महोत्सव से लोगों को जोड़ने का प्रयास सिटी चीप दैनिक अखबार में विशेष रूप से प्रसारण किया गया जिससे महा उत्सव का सफल आयोजन हुआ इस आयोजन में मध्य प्रदेश के मंत्री एवं सासाकी ए अधिकारियों की एक अच्छी साझेदारी थी जिससे नर्मदा महोत्सव मैं लोगों का उत्साह है एवं अधिक से अधिक संख्या का पहुंचना नर्मदा पूजन एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम में समा

बांध दिया था उसे संबंध में आज दिनांक 17 - 2 - 2025 को कलेक्टर सभागार में अनूपपुर जिले के पत्रकार सुशील सोनी को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया इसमें जनसंपर्क कार्यालय अनूपपुर के समस्त अधिकारी की भूमिका रही.

अवैध मुरूम परिवहन करते डंपर को खनिज अधिकारी ने पकड़ा

खरगोन कसरावद थाना क्षेत्र के अवैध मुरुम लदे एक डंपर को खनन विभाग ने मंगलवार को जप्त किया है मंडलेश्वर रोड़ पर एक डंपर MP 04 HE 5841 को खनन विभाग के अधिकारी जांच के लिए रोका मुरुम से संबंधित कागजात की मांग की गयी। लेकिन चालक के द्वारा किसी प्रकार की माइनिंग रॉयल्टी नहीं दिखाई गई। जिसके बाद खनिज विभाग की अधिकारी प्रियंका अजनारे ने परिवहन करते पकड़ा और पकड़कर कसरावद पुलिस थाने की अभीरक्षा में खड़ा किया गया खनिज अधिनियम की धारा के अंतर्गत कार्रवाई की गई है।

महानिरीक्षक/पुलिस अधीक्षक धार श्री मनोज कुमार सिंह के निर्देशन में सायबर सेल धार टीम को तेलंगाना राज्य के नालगोण्डा जिले में 25 लाख रुपये की चोरी कर फरार हुवे आरोपी अशरफ को 25 लाख रुपये नगदी व वाहन सहित पकडने में मिली महत्वपूर्ण

धार

धार पुलिस को तेलंगाना राज्य में 25 लाख रुपये की चोरी कर फरार हुए आरोपी को पकडने में मिली महत्वपूर्ण सफलता। धार पुलिस को आरोपी के कब्जे से 25 लाख रुपये व घटना में प्रयुक्त कार को बरामद करने में मिली महत्वपूर्ण सफलता। तेलंगाना राज्य में 25 लाख रुपये की चोरी कर फरार हुआ था आरोपी अशरफ। धार पुलिस की मुखबिर सूचना के आधार पर पकडा गया आरोपी अशरफ। पूर्व में आरोपी अशरफ के विरुद्ध पुणे (महाराष्ट्र) एवं थाना सिमरोल जिला इंदौर में चोरी व थाना

मनावर में मारपीट संबंधी अपराध दर्ज हैं। पुलिस उप महानिरीक्षक/पुलिस अधीक्षक धार श्री मनोज कुमार सिंह द्वारा तेलंगाना राज्य के जिला नालगोण्डा के थाना नारकट पल्ली के अपराध क्रमांक 37/2025 धारा 305 (ष) ब्क्हस् में फरियादी से चैन्नई से हैदराबाद जाने वाली बस में से 25 लाख रुपये से भरे बैग चोरी के कर फरार हुवे आरोपी अशरफ निवासी खेरवा जागीर थाना मनावर जिला धार की धड़पकड़ हेतु अनुविभागीय अधिकारी पुलिस मनावर श्रीमति अनु बेनिवाल (भा.पु.से.) के नेतृत्व में सायबर सेल धार प्रभारी प्रशांत गुंजाल को आवश्यक दिशा निर्देश जारी कर उचित कार्यवाही हेतु लगाया गया था। इसी तारतम्य में सायबर सेल धार टीम व तेलंगाना पुलिस टीम के साथ मिलकर विश्वसनीय मुखबिर से सूचना के आधार पर तेलंगाना राज्य के जिला नालगोण्डा के थाना नारकट पल्ली के अपराध क्रमांक 37/2025 धारा 305 (ष) ब्क्हस् के फरार आरोपी अशरफ खान पिता हाजी रोशन मुस. उम्र 42 वर्ष निवास खेरवा जागीर थाना मनावर जिला धार को पकडकर आरोपी अशरफ व्दारा चोरी किये गये 25 लाख रुपये नगदी व घटना में प्रयुक्त की गई कार क्रमांक रूक्क-09-ष्ठ-9680 बरामद करने में महत्वपूर्ण सफलता हासिल की गई।

गिरफ्तार आरोपी का नाम 1. अशरफ खान पिता हाजी रोशन मुस. उम्र 42 वर्ष निवास खेरवा जागीर थाना मनावर जिला धार

जप्त मश्रुका का विवरण 1 आरोपी अशरफ के कब्जे से 25 लाख रुपये नगदी व कार क्रमांक MP-09-D-9680 कुल मश्रुका कीमत 35,0000/- रुपये आरोपी अशरफ को गिरफ्तार करने में आर. राघवेन्द्र व तेलंगाना राज्य के निरीक्षक जितेन्द्र रेड्डी व उनकी टीम की महत्वपूर्ण भूमिका रही।

राष्ट्र हित के रहे अग्रसर - ममता दीदी

तारोद में सम्पन्न हुआ यज्ञ ओर कथा, विधायक पहुंचे

उज्जैन

आज की युवा पीढ़ी को चाहिए क्यों राष्टहित में अग्रसर रहे राष्टहित के लिए हम सभी को मिलकर आगे हाथ बढ़ाना चाहिए, अगर कोई राष्टहित समाज हित या गांव के हित में काम होते हैं तो उसमें अपने निहित स्वार्थ को छोड़ना चाहिए, ऐसे कार्यों में अग्रणी रहना चाहिए ना कि उन कार्यों में बाधा डालने का काम करना चाहिए यह बात तोड़ा में चल रही सप्त दिवसीय श्री राम कथा पंच कुंडी सप्त देवासी श्री विष्णु महायज्ञ के समापन के अवसर पर कथा व्यास पीठ से सुश्री ममता पाठक ने कही कथा में आपने बताया कि श्री राम कथा के भगवान राम के चरित्र का सुंदर वर्णन किया इस दौरान तारों सहित आसपास के गांव से सैकड़ो की संख्या में भक्तजन कथा सुनने पहुंचे अंतिम दिवस तोड़ा और आसपास के गांव के साथी क्षेत्र के विधायक डॉक्टर तेज बहादुर सिंह चौहान भी पहुंचे जिन्होंने भंडारे में प्रसाद प्राप्त करते हुए वहां उपस्थित जन समुदाय को भोजन करवाने के मदद भी की ! ग्रामीणों ने बताया कि विधायक जी यहां काफी समय तक रुके ग्रामीणों को बात को सुना भी सही और उनके निराकरण के लिए स्पष्ट भी किया !

कटनी में गिद्धों की गणना शुरू, वन विभाग जुटा संरक्षण प्रयासों में

सुनील यादव । सिटी चीफ

गिद्ध एक ऐसा पक्षी है, जिसका हमारे धर्म ग्रंथों में भी उल्लेख मिलता है, रामायण में जटायु को कौन नहीं जानता है। हमारे प्रकृति में गिद्ध एक अहम रोल भी निभाते हैं, इन्हें सफाई कर्मी पक्षी के नाम से भी जाना जाता है। भारत देश में ही गिद्धों की कई प्रजातियां पाई जाती हैं, तो वहीं इन प्रजातियों में से अधिकतर प्रजाति मध्य प्रदेश में भी मिलती हैं। कटनी जिले के विजयराघवगढ़ और रीठी की पहाड़ियों में भी गिद्धों की काफी संख्या है। अब एक बार फिर से गिद्धों की गणना कटनी में शुरू हो चुकी है। जहां से फिर से इनकी संख्या बढ़ने का अनुमान है।

कटनी जिले के वन क्षेत्रपाल नवी अहमद खान ने बताया कि कटनी जिले के वन परिक्षेत्र के पहाड़ियों में गिद्धों की गणना शुरू हो चुकी है। 17-18 और 19 फरवरी को कटनी जिले में वन परिक्षेत्र के सभी बीट में गिद्धों की गणना की जा रही है। इसके लिए जितने भी सभी अधिकारी-कर्मचारी हैं, उन्हें गिद्धों की विभिन्न प्रजातियों की पहचान और गिनती के तरीकों के लिए अलग से ट्रेनिंग भी दी गई है। जितनी भी गणना होगी,उसमें सभी अधिकारी और कर्मचारी अपने-अपने क्षेत्र में मिलने वाले गिद्धों की संख्या उनकी प्रजातियों का पूरा डाटा एक विशेष प्रपत्र में भरेंगे।

विधायक सोहागपुर, कलेक्टर सहित अन्य अधिकारी रहे उपस्थित

नर्मदापुरम

शहरी भूमि रिकार्ड के डिजिटलीकरण के लिए ''नक्शा'' परियोजना का शुभारंभ माखननगर में आयोजित हुआ जिला स्तरीय कार्यक्रम

भारत सरकार की महत्वपूर्ण ''नक्शा'' परियोजना का आज माखननगर में शुभारंभ किया गया। इस परियोजना के अंतर्गत शहरी भूमि रिकार्ड का डिजिटलीकरण किया जाएगा, जिससे भूमि से संबंधित प्रक्रियाएँ पारदर्शी, तेज और सटीक होंगी। इस परियोजना से भारत के 152 शहरों में शहरी भूमि रिकार्ड को डिजिटलीकरण के माध्यम से उपलब्ध कराया जाएगा, जिनमें मध्यप्रदेश के 10 शहरों में माखननगर भी शामिल है। नक्शा परियोजना की शुरुआत से नागरिकों को भूमि रिकार्ड की ऑनलाईन उपलब्धता मिल सकेगी। इस योजना का उद्देश्य भूमि रिकार्ड्स की अनुपलब्धता, सरकारी दस्तावेजों और वास्तविक भूमि स्वामित्व में अंतर, स्वामित्व विवाद, और अवैध कब्जे जैसी समस्याओं को दूर करना है। इससे भूमि संबंधित कार्यों में पारदर्शिता आएगी और नागरिकों को सीधा लाभ मिलेगा। कलेक्टर सोनिया मीना ने इस परियोजना की महत्ता पर प्रकाश डालते हुए कहा, ''नक्शा परियोजना के शुभारंभ से माखननगर जिले में भूमि रिकार्ड का डिजिटलीकरण होगा, जो शहरी भूमि प्रशासन को और अधिक पारदर्शी और कुशल बनाएगा। इससे न केवल भूमि विवादों का समाधान होगा, बल्कि नागरिकों को सुविधाजनक और समय पर भूमि रिकार्ड प्राप्त होंगे। यह परियोजना प्रदेश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देगी और लोगों की समस्याओं को दूर करने में सहायक होगी। कार्यक्रम के शुभारंभ अवसर पर सोहागपुर विधायक ठा. विजयपाल सिंह, कलेक्टर सोनिया मीना, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व नर्मदापुरम नीता कोरी, सिटी मजिस्ट्रेट श्री बृजेन्द्र रावत, नर्मदापुरम तहसीलदार श्री देव शंकर धुर्वे, नगर परिषद अध्यक्ष रीना आकाश तिवारी, जनपद अध्यक्ष सावित्री परनामे, माखननगर तहसीलदार अनिल पटैल और अन्य अधिकारी एवं गणमान्य नागरिक उपस्थित थे।

24 घंटे आपको मिलेगा स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ

उपस्वास्थ्य केंद्र के भूमि पूजन पर बोले सासंद फिरोजिया

उज्जैन

शासन को मंशा है कि गांवों में भी प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं के लाभ 24 घंटे मिले और इसको ध्यान में रखकर ही गांव गांव में सर्व सर्वसुविधायुक्त उपस्वास्थ्य केंद्र बनाने का कार्य हो रहा है, इन उपस्वास्थ्य केंद्रों में प्राथमिक चिकित्सा के साथ स्टाफ के कुछ सदस्यों के रहने की व्यवस्था भी रहेगी जो 24 घंटे उपस्वास्थ्य केंद्र पर उपस्थित रहेंगे और ग्रामीणों को 24 घंटे प्राथमिक उपचार मिल सके यह बात भैंसोला में 65 लाख की लागत से बनने वाले उप स्वास्थ्य केंद्र, ओर मुख्यमंत्री अधोसंरचना के तहत 5 लाख रुपए की लागत से बनने वाली पुलिया के भूमि पूजन कार्यक्रम में मुख्य अतिथि क्षेत्र के सांसद अनिल फिरोजिया ने कही ! कार्यक्रम में संबोधित करते हुए सांसद फिरोजिया ने कही कि सभी विभागों में कार्यरत अधिकारी कर्मचारियों को अपने अपने विभागों के समय पर उपस्थित रहने की बात कही ओर साथ ही कहा कि अगर नहीं ऐसा नहीं होता है, तो फिर उनके खिलाफ कार्यवाही भी होगी, कार्यक्रम की अध्यक्षता विधायक डॉ तेजबहादुरसिंह चौहान, जिलाध्यक्ष राजेश धाकड़, जिला पंचायत सदस्य प्रतिनिधि गजेन्द्रसिंह सोलंकी, लालसिंह राणावत, श्रीमती श्यामुबाई गट्टुलाल चंद्रवंशी, पर्वतसिंह सोलंकी, मांगीलाल पाटीदार, धर्मेन्द्र पाटीदार, रामलाल धाकड़, लालसिंहजी बंजारी मंचासिन रहे ! कार्यक्रम में रामलाल धाकड़, गजेन्द्रसिंह लोहचितारा, संतोष नावटिया, बाबूलाल पटेल, दीपक धाकड़, अनोखीलाल पाटीदार, भरत पांचाल, प्रकाश गुर्जर, जयपालसिंह पंवार, छोटे राजा पंवार, विक्की बना, मोहनसिंह बंजारी, भैंसोला सरपंच बलवंतसिंह पंवार, सचिव जीवनसिंह पंवार सहायक सचिव टीना पंवार, गोरधन धाकड़, प्रभुलाल धाकड़, श्यामलाल बोडाना, समस्त पंचगण एवं ग्राम पंचायत भैंसोला के समस्त ग्रामवासी उपस्थित थे !

नए सर्वे में स्वय कर सकते है आवेदन - विधायक कार्यक्रम में संबोधित करते हुए विधायक डॉ तेजबहादुरसिंह चौहान ने बताया कि वर्तमान में विधानसभा क्षेत्र के 5 हजार से अधिक आवास को मंजूरी मिली है, जिससे सभी पात्र परिवारों को पक्का मकान मिल सकेगा, साथ ही जिनका सर्वे सूची के नाम नहीं है तो वर्तमान में नए नाम जोड़ने की प्रक्रिया भी चल रही है आप स्वय भी मोबाइल एप्स के जरिए पीएम आवास योजना की सूची में नाम जोड़ सकते है !

भैंसोला से मीण ओर भैंसोला से घिनौदा रोड बने कार्यक्रम में संबोधित करते हुए पूर्व जनपद उपाध्यक्ष लालसिंह बंजारी ने सांसद ओर विधायक दोनो से ही भैंसोला से मीण ओर भैंसोला बनाने की मांग की बंजारी ने बताया कि यह दोनों मार्ग अति आवश्यक है और उनके बनने से कई परिवारों को आवागम में सुविधा होगी !

कंचनखेड़ी में हुआ भूमि पूजन - बसूला में भूमि पूजन के बाद सारे जनप्रतिनिधि कंचनखेड़ी ग्राम पंचायत के कुटलाना में पहुंचे, यहां कुलथाना में आंगनबाड़ी भवन और सीसी रोड का भूमि पूजन अतिथियों के द्वारा किया गया इस दौरान समस्त अतिथियों के साथ ग्राम पंचायत सरपंच सचिव सहायक सचिव उप सरपंच और ग्रामीण जनता उपस्थित रही !

कलेक्टर श्री सुभाष कुमार द्विवेदी की अध्यक्षता में आज कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में समय सीमा के लंबित पत्रों की समीक्षा आयोजित की गई

अशोकनगर

बैठक में निर्देश दिए कि सीएम हेल्पलाईन पोर्टल पर संबंधित विभागों से संबंधित प्राप्त शिकायतों को प्राथमिकता के साथ निराकरण कर प्रगति लाई जाएं। साथ ही 100 दिवस से ऊपर एवं 50 दिवस से अधिक शिकायतों का निराकरण किया जाए।

बैठक में कलेक्टर श्री द्विवेदी ने निर्देशित किया सीएम हेल्पलाईन की एक-एक शिकायतों को देखे और उनका निराकरण तत्परता के साथ करें। उन्होंने समाधान ऑनलाईन से संबंधित विषयों पर विभागवार समीक्षा कर निराकरण हेतु अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने जिले में आश्रय स्थलों के निर्माण हेतु प्रस्ताव भेजे जाने के निर्देश सीईओ जनपद पंचायत एवं सीएमओ नगरीय निकाय को दिए। उन्होंने आगामी 24 फरवरी को किसान सम्मान निधि की राशि किसानों के खातों में अंतरित किये जाने हेतु जिला स्तरीय कार्यक्रम कृषि विज्ञान केन्द्र में आयोजित किये जाने हेतु उप संचालक कृषि को निर्देशित किया। उन्होंने जिले में राजस्व वसूली किये जाने तथा गिरदावरी को बढाये जाने के निर्देश राजस्व अधिकारियों को दिए। उन्होंने समग्र पोर्टल पर संबल एवं संनिर्माण कर्मकार मण्डल में पात्र हितग्राहियों को सर्वे कर जोडे जाने के निर्देश अधिकारियों को दिए.उन्होंने निर्देशित किया कि जिले में पीएम जनमन योजनान्तर्गत निर्माणाधीन आवासों का निरीक्षण एक सप्ताह में किया जाकर जांच रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए। उन्होंने सिविल सूट के मामलों में आवश्यक कार्यवाही कर जबाव प्रस्तुत किये जाएं।

बैठक में आगामी 28 फरवरी को शासकीय नेहरू महाविद्यालय अशोकनगर में जिला स्तरीय युवा संगम कार्यक्रम अंतर्गत युवाओं को जॉब फेयर हेतु अधिक से अधिक कंपनियों को आमंत्रित किया जाए। साथ ही युवा संगम कार्यक्रम का अधिक से अधिक प्रचार-प्रसार कराया जाए। बैठक में किसान सम्मान निधि,खनिज की रायल्टी वसूली,निर्माण कार्यो की प्रगति एवं गुणवत्ता के संबंध में विस्तार से समीक्षा कर आवश्यक निर्देश दिए। बैठक में पेयजल की समीक्षा करते हुए निर्देशित किया कि पेयजल की समीक्षा हेतु जनपद स्तर पर बैठकों का आयोजन कर नल जल योजना,हेण्डपम्प खनन तथा पेयजल की विस्तृत कार्ययोजना की समीक्षा की जाए। यह बैठकें मुंगावली एवं अशोकनगर में 19 फरवरी को,ईसागढ़ में 20 फरवरी तथा चंदेरी में 21 फरवरी आयोजित होगी।

सफलता की कहानी

जनसुनवाई में कलेक्टर ने सुनी 114 आवेदकों की समस्याएं, निराकरण के दिए निर्देश

सीधी

अनिल को ट्राइसाइकिल तथा लवकुश को वैशाखी मिलने से चेहरे में मुस्कान आई

नागरिकों के समस्याओं के त्वरित निराकरण के लिये शासन के निर्देशानुसार प्रत्येक मंगलवार को जिला पंचायत सभागार में सुबह 11 बजे से दोपहर 01 बजे तक जनसुनवाई आयोजित की जाती है। इस बार आयोजित जनसुनवाई में कलेक्टर स्वरोचिष सोमवंशी द्वारा जिले के विभिन्न अंचलों से आए 114 आवेदकों की समस्याओं को ध्यानपूर्वक सुनते हुए संबंधित अधिकारियों से संपर्क कर शिकायत की वस्तुस्थिति की जानकारी प्राप्त की गई तथा उसके निराकरण के लिए निर्देश दिए गए। अनिराकृत आवेदनों के लिये समय-सीमा निर्धारित कर अधिकारियों को समय-सीमा में निराकरण करने के निर्देश दिए गए हैं।जनसुनवाई में जनपद पंचायत सिहावल के ग्राम बेलहा से आये अनिल शाह ने अपने आवेदन पत्र के माध्यम से बताया कि जन्म से पैर से दिव्यांग होने के कारण चल नहीं पाता यदि ट्राइसाइकिल मिल जाए तो समस्या का निराकरण हो जाये। इसी प्रकार जनपद पंचायत सिहावल के ग्राम हटवा से आए लवकुश साकेत ने बताया कि पैर में दिक्कत होने के कारण कहीं आने जाने में समस्या हो रही है। कलेक्टर ने शिकायत का तत्काल निराकरण सामाजिक न्याय विभाग से कराया। साथ ही उनकी शारीरिक की स्थिति को देखते हुए अनिल को ट्राई साइकिल और लवकुश को वैशाखी प्रदान कराई। आज समस्या का त्वरित निराकरण होने पर अनिल और लवकुश खुश और संतुष्ट दिखे। इस अवसर पर उपखण्ड अधिकारी गोपद बनास नीलेश शर्मा सहित जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे। आज आयोजित जनसुनवाई में समस्त उपखण्ड अधिकारी, तहसीलदार और मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत भी वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से जिला स्तरीय जनसुनवाई से जुड़े रहे।

कलेक्टर श्री सिंह ने जीआईएस तैयारियों की समीक्षा बैठक

भोपाल

कलेक्टर श्री कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने मंगलवार को जिला पंचायत सभागार में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट (जीआईएस) की तैयारियों को लेकर समीक्षा बैठक की। इस बैठक में विभागीय अधिकारियों को सौंपे गए दायित्वों की प्रगति की समीक्षा की गई और उन्हें समय - सीमा के भीतर समस्त तैयारियां पूर्ण करने के निर्देश दिए गए। बैठक में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के आगमन को लेकर की जा रही तैयारियों पर विशेष जोर दिया गया। स्टेट हेंगर, एयरपोर्ट, वीवीआईपी सुरक्षा, यातायात प्रबंधन, आयोजन स्थल की व्यवस्थाएं, साफ-सफाई, सौंदर्यीकरण, अतिथियों के ठहरने और स्वागत से जुड़ी तैयारियों की विस्तार से समीक्षा की गई। कलेक्टर ने नगर निगम, पुलिस प्रशासन, लोक निर्माण विभाग, स्मार्ट सिटी प्रबंधन एवं अन्य विभागों को निर्देशित किया कि प्रधानमंत्री जी के आगमन और समिट के सफल आयोजन के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करें। उन्होंने एयरपोर्ट राज भवन एवं आयोजन स्थल तक यातायात के सुचारू संचालन, पार्किंग आदि को उच्च स्तर पर बनाए रखने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने सभी अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रधानमंत्री जी के आगमन और समिट के सफल आयोजन को लेकर पूरी प्रतिबद्धता और समन्वय के साथ कार्य करें ताकि यह आयोजन सफलता के साथ सम्पन्न हो। बैठक में नगर निगम आयुक्त श्री हरेन्द्र नारायण, एडीएम श्री सिद्धार्थ जैन, सीईओ जिला पंचायत श्रीमती इला तिवारी, सीईओ स्मार्ट सिटी श्रीमती अंजू अरुण कुमार सहित सभी संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।

भारत के 50% लोग शेख हसीना के रहने से नाराज

कहा- चली जाएं वापस, बांग्लादेशी हिंदुओं पर भी दी राय

इंटरनेशनल डेस्क: हाल ही में भारत में हुआ एक सर्वेक्षण यह दर्शाता है कि भारत के अधिकांश लोग बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के बारे में नकारात्मक सोच रखते हैं और चाहते हैं कि वह भारत छोड़कर चली जाएं। मूड ऑफ द नेशन सर्वे में यह तथ्य सामने आया है कि 50.2% भारतीयों का मानना है कि शेख हसीना को भारत छोड़ देना चाहिए । वहीं, 21.1% लोगों का कहना है कि हसीना को बांग्लादेश वापस भेज दिया जाए , और 29.1% लोग चाहते हैं कि उन्हें किसी तीसरे देश

में स्थानांतरित किया जाए । सर्वे के मुताबिक, भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में हसीना के प्रति नाराजगी ज्यादा देखी जा रही है। इन राज्यों के नागरिकों का कहना है कि बांग्लादेश के साथ उनकी सीमा साझा होने की वजह से हसीना के कारण उत्पन्न उथलपुथल का उन पर सीधा असर पड़ा है । इन राज्यों में 55त्न लोग चाहते हैं कि शेख हसीना को वापस बांग्लादेश भेजा जाए। इन क्षेत्रों में हसीना के खिलाफ काफी आक्रोश है, क्योंकि यहां की जनता बांग्लादेश की राजनीतिक घटनाओं से गहरे प्रभावित महसूस करती है।

इसके अलावा 16त्न लोग चाहते हैं कि हसीना को किसी तीसरे देश में भेज दिया जाए ताकि भारत और बांग्लादेश के रिश्ते अच्छे बने रहें और हसीना को कानूनी कार्रवाई से भी बचाया जा सके । हालांकि 23% लोग मानते हैं कि हसीना को भारत में शरण दी जानी चाहिए क्योंकि उनके साथ पुराने अच्छे रिश्ते रहे हैं। यह सर्वे 2024 के जुलाई में हुए बांग्लादेश के विद्रोह के बाद हुआ था, जब शेख हसीना भारत में शरण लेने आई थीं। 5 अगस्त 2024 को हसीना अपनी बहन रेहाना के साथ भारत पहुंचीं, जब बांग्लादेश में छात्रों ने उनके शासन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। भारत में शरण लेने के बाद से हसीना के खिलाफ भारतीय नागरिकों के बीच प्रतिक्रिया मिश्रित रही है।सर्वे में 37.6% लोग मानते हैं कि शेख हसीना भारत की पक्की दोस्त रही हैं, इसलिए उन्हें भारत में शरण मिलनी चाहिए। वहीं, 33% लोग यह मानते हैं कि भारत ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हुए हिंसक हमलों के खिलाफ कड़ी प्रतिक्रिया नहीं दी, इसलिए हसीना को लेकर भारत को सक्रिय कदम उठाने चाहिए। बांग्लादेश में शेख हसीना के खिलाफ 100 से ज्यादा मुकदमे दर्ज किए गए हैं, जिनमें हत्या, सामूहिक हत्या और मानवता के खिलाफ अपराध जैसे गंभीर आरोप शामिल हैं। इसके बावजूद हसीना ने भारत में शरण ली है, जबकि बांग्लादेश सरकार ने 23 दिसंबर 2024 को भारत से औपचारिक रूप से शेख हसीना को वापस भेजने का अनुरोध किया था। इस मुद्दे पर भारत ने अब तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है जिससे दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ रहा है। यह सर्वेक्षण इस बात को भी उजागर करता है कि बांग्लादेश और भारत के रिश्तों में एक नया विवाद उत्पन्न हो सकता है, क्योंकि शेख हसीना की वापसी पर दोनों देशों के बीच राय में अंतर है। इस विवाद ने दोनों देशों में राजनीतिक चर्चा को और तेज कर दिया है, और हसीना का भविष्य अब तक अस्पष्ट बना हुआ है।

पाकिस्तान में सेना के ट्रकों के काफिले पर आंतकी हमला

लूटपाट कर जलाए वाहन, 4 सैनिकों की मौत

इंटरनेशनल डेस्क: अशांत उत्तर-पश्चिम क्षेत्र में पाकिस्तानी सेना की राहत सामग्री ले जा रहे ट्रकों पर पहले हुए हमले का जवाब दे रहे सुरक्षा बलों पर रात में घात लगाकर आतंकवादियों ने हमला कर दिया और इस बीच हुई गोलीबारी में चार सैनिक मारे गए। अधिकारियों ने मंगलवार को यह जानकारी दी। यह हमला अशांत खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के कुर्रम जिले में राहत सामग्री ले जा रहे ट्रकों के काफिले पर सोमवार को हुए हमले के जवाब में अधिकारियों द्वारा अतिरिक्त बल भेजे जाने के कुछ ही घंटों बाद हुआ। ट्रकों पर किए गए हमले में एक चालक और सुरक्षा अधिकारी की मौत हो गई थी।

अधिकारियों ने बताया कि कुर्रम में रात भर हुए हमले में कुछ सुरक्षा कर्मी भी घायल हुए हैं। यहां हाल के महीनों में शिया और सुन्नी कबीलों के बीच झड़पों में कम से कम 130 लोग मारे गए हैं। अधिकारियों ने बताया कि कुर्रम के मुख्य शहर पाराचिनार की ओर जा रहे कई ट्रकों को लूट लिया गया और जला दिया गया। पाराचिनार के एक अस्पताल के चिकित्सक कैसर अब्बास ने बताया कि उन्हें सोमवार रात कुर्रम से चार जवानों के शव मिले। वहीं प्राधिकारियों ने बताया कि हमलों के दोषियों को पकड़ने के लिए बड़े पैमाने पर अभियान की योजना बनाई जा रही थी। फिलहाल किसी भी समूह ने इस हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है, लेकिन सुन्नी उग्रवादियों पर संदेह जताया जा रहा है। कुर्रम के कुछ हिस्सों में शिया मुसलमानों का वर्चस्व है, हालांकि वे पाकिस्तान के शेष हिस्सों में अल्पसंख्यक हैं, जहां सुन्नी बहुसंख्यक हैं। इस क्षेत्र में सांप्रदायिक संघर्ष

का इतिहास रहा है, जहां उग्रवादी सुन्नी समूह पहले अल्पसंख्यक शियाओं को निशाना बनाते थे।

पुलिस के वाहन पर हमला, गोलीबारी में आतंकवादी ढेर

खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में पुलिस की मोबाइल वैन पर हथगोले से किए गए हमले में पुलिस का एक कर्मी घायल हो गया और जवाबी गोलीबारी के दौरान एक आतंकवादी मारा गया। मीडिया की एक खबर में मंगलवार को यह जानकारी दी गई। 'जियो न्यूज% की खबर के अनुसार, यह हमला कोहाट जिले के शादीपुर इलाके में किया गया। खबर में अधिकारियों के हवाले से कहा गया है कि घात लगाकर किए गए इस हमले में पुलिस का एक कर्मी घायल हो गया जबकि जवाबी गोलीबारी में एक आतंकवादी मारा गया। हमले के बाद कई आतंकवादियों को गिरफ्तार कर लिया गया और उनके पास से हथगोले और अन्य हथियार बरामद किए गए। खबर में कहा गया है कि हमले में शामिल आतंकवादियों के बारे में खुफिया जानकारी प्राप्त करने के लिए तलाशी अभियान जारी है। पाकिस्तान में आतंकी हमलों में बढ़ोतरी हुई है और वह नियमित रूप से तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (टीटीपी) के खतरे से निपटने में निष्क्रियता के लिए अफगान सरकार को दोषी ठहराता है। आतंकवाद के मुद्दे पर इस्लामाबाद और काबुल के बीच संबंध खराब हो गए हैं।

इधर, सऊदी अरब में जेलेंस्की टीम के बिना शांति वार्ता शुरू, उधर रूस ने यूक्रेन पर कर दिए 176 ड्रोन हमले

इंटरनेशनल डेस्क: सऊदी अरब में यूक्रेनी अधिकारियों को दरकिनार कर 18 फरवरी को रूस और अमेरिका के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक हुई, जिसमें यूक्रेन युद्ध को समाप्त करने पर बातचीत शुरू की गई। यह बैठक रियाद के दिरियाह पैलेस में हुई। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो और रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव के नेतृत्व में दोनों देशों के प्रतिनिधिमंडल ने बातचीत की। इस मुलाकात का उद्देश्य रूस और अमेरिका के रिश्तों को सुधारना और यूक्रेन युद्ध को समाप्त करने के लिए रास्ता तैयार करना था। यह कदम ट्रंप प्रशासन द्वारा रूस को अलग-थलग करने की नीति को बदलने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। बैठक का उद्देश्य अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच एक बैठक का रास्ता खोलना है। रूस और अमेरिका के बीच यह वार्ता यूक्रेन युद्ध को लेकर एक नए मोड़ की शुरुआत हो सकती है, जबकि यूक्रेनी अधिकारियों को इसमें शामिल नहीं किया गया।इस वार्ता के बीच रूस ने यूक्रेन पर 176 ड्रोन से हमला किया, जिससे इलाके में तबाही मच गई। यूक्रेनी सेना ने दावा किया कि रूस ने 176 ड्रोन से हमला किया है, जिसमें 38 अपार्टमेंटों को खाली करना पड़ा और एक बच्चा गंभीर रूप से घायल हुआ, जिसे अस्पताल में भर्ती किया गया। यूक्रेनी सेना के अनुसार, उनकी एयरफोर्स ने 103 ड्रोन मार गिराए, जबकि 67 ड्रोन अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंचे। कुछ

जगहों पर गिरने के कारण ड्रोन से आग लग गई, जिससे और अधिक नुकसान हुआ। हालांकि, रूस ने इस हमले पर अभी तक कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है। सऊदी अरब के दिरियाह पैलेस में सोमवार को रूस और अमेरिका के शीर्ष अधिकारी एक-दूसरे से मिले। यह बैठक यूक्रेन में युद्ध समाप्त करने और रूस-अमेरिका संबंधों में सुधार करने के उद्देश्य से आयोजित की गई थी। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार माइक वाल्ट्ज, और विशेष दूत स्टीव विटकॉफ ने इस वार्ता में हिस्सा लिया। रूस की ओर से विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव और पुतिन के विदेश मामलों के सलाहकार यूरी उशाकोव शामिल हुए। यह बैठक अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच होने वाली संभावित बैठक का मार्ग प्रशस्त करने का प्रयास है। ट्रंप ने हाल ही में यह घोषणा की थी कि वह और पुतिन यूक्रेन युद्ध को समाप्त करने के लिए बातचीत करने पर सहमत हो गए हैं। इसके बाद, अमेरिकी सरकार ने रूस के साथ अपने रिश्तों को नए तरीके से स्थापित करने की योजना बनाई है। हालांकि, इस वार्ता में यूक्रेनी अधिकारियों को शामिल नहीं किया गया। यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की ने कहा कि यदि कीव को इस वार्ता में शामिल नहीं किया गया, तो उनका देश इसके परिणामों को स्वीकार नहीं करेगा। यूक्रेनी सरकार ने यह स्पष्ट किया कि वे रूस के साथ बातचीत में किसी भी तरह की संलिप्तता के लिए सहमत नहीं हैं, अगर उनका देश इस प्रक्रिया से बाहर रखा जाए। यह वार्ता यूक्रेन युद्ध के बाद अमेरिका और रूस के बीच बने तनाव को कम करने के लिए एक प्रयास मानी जा रही है। यूक्रेन में युद्ध शुरू होने के बाद, अमेरिका और रूस के रिश्ते अत्यधिक खराब हो गए थे और यह दशकों में सबसे निचले स्तर पर पहुंच गए थे।

सात महीने की बच्ची को किडनैप कर किया था रेप, कोर्ट ने दी फांसी की सजा

नेशनल डेस्क. मानवता को शर्मसार करने वाली एक घटना में, एक 37 वर्षीय व्यक्ति ने 7 महीने की मासूम बच्ची का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म किया और उसे मारने का प्रयास किया। इस घिनौने अपराध के लिए अदालत ने दोषी को फांसी की सजा सुनाई है। यह मामला कोलकाता के बड़तल्ला इलाके में 30 नवंबर 2024 को हुआ था। आरोपी राजीव घोष ने बच्ची को उस समय अगवा किया जब वह अपनी मां के साथ सड़क पर थी। इसके बाद उसने बच्ची के साथ दुष्कर्म किया और उसे मरने के लिए छोड़ दिया।

त्वरित कार्रवाई, न्याय की मिसाल

पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए आरोपी को 5 दिसंबर को गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद 75 दिनों के भीतर अदालत ने मामले की सुनवाई पूरी कर दोषी को फांसी की सजा सुनाई। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि यह अपराध %दुर्लभतम में दुर्लभ% श्रेणी का है और ऐसे मामलों में अधिकतम सजा देना ही न्यायसंगत होगा।

बच्ची का संघर्ष जारी

पीड़ित बच्ची का अभी भी कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में इलाज चल रहा है। इस घटना ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है और लोगों में आक्रोश है। यह पश्चिम बंगाल में पिछले छह महीनों में अदालत द्वारा सुनाई गई सातवीं मौत की सजा है। यह पोक्सो कानून के तहत यौन अपराध के मामले में छठा मृत्युदंड है।

झारखंड के लाखों बेरोजगार युवा जुमलेबाजी नहीं अपना हक और अधिकार चाहते हैं: बाबूलाल मरांडी

झारखंड में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर बड़ा निशाना साधा। मरांडी ने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत ने कुछ 100-200 युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपा, करोड़ों रुपये खर्च कर भव्य आयोजन किया गया।

झारखंड के लाखों बेरोजगार युवाओं के कुछ सवाल हैं

मरांडी ने कहा कि हेमंत जी के चाटुकारों द्वारा सबसे यादा नौकरी देने वाले मुख्यमंत्री का ढोल भी पीटा जाएगा। मरांडी ने कहा कि झारखंड के लाखों बेरोजगार युवाओं के कुछ सवाल हैं, जो अब भी अनसुलझे हैं। मरांडी ने पूछा कि प्रतियोगी परीक्षा कैलेंडर कब जारी होगा जेपीएससी अध्यक्ष की नियुक्ति कब होगी?, जेएसएससी, सीजीएल पेपर लीक की जांच कहां तक पहुंची। मरांडी ने पूछा कि मुख्यमंत्री जी बताएं किस नियोजन नीति के तहत नियुक्तियां कर रहे हैं? झारखंड

के युवाओं को कितना आरक्षण दिया गया? मरांडी ने कहा कि हेमंत जी, युवाओं का भविष्य पीआर स्टंट और दिखावों से नहीं, बल्कि पारदर्शिता और जवाबदेही से संवरेगा। झारखंड के लाखों बेरोजगार युवा जुमलेबाजी नहीं, बल्कि अपना हक और अधिकार चाहते हैं।

रूस-यूक्रेन युद्ध में नया मोड़

सऊदी में हाई-प्रोफाइल बैठक बाद रूस का ऐलान- पुतिन बातचीत को तैयार लेकिन..

इंटरनेशनल डेस्क: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सत्ता में लौटने के बाद रूस-यूक्रेन युद्ध को लेकर नया घटनाक्रम सामने आया है। मंगलवार को रूस ने बड़ा बयान दिया कि राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन जरूरत पड़ने पर यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की से बातचीत करने के लिए तैयार हैं। हालांकि, रूस ने जेलेंस्की की वैधता पर भी सवाल उठाए हैं और कहा है कि सुरक्षा के व्यापक मुद्दों पर चर्चा किए बिना युद्ध का हल संभव नहीं है। क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेसकोव

ने मीडिया से कहा, पुतिन पहले ही कह चुके हैं कि अगर जरूरत पड़ी तो वे जेलेंस्की से बातचीत करेंगे।

हालांकि, उन्होंने यह भी जोड़ा कि किसी भी समझौते के लिए कानूनी आधार पर चर्चा होनी जरूरी है क्योंकि जेलेंस्की की वैधता को लेकर सवाल उठ सकते हैं। गौरतलब है कि यूक्रेनी संविधान के अनुसार , युद्धकाल (मार्शल लॉ) के दौरान राष्ट्रपति चुनाव नहीं कराए जा सकते। जेलेंस्की का पांच साल का कार्यकाल 2024 में समाप्त हो चुका है, लेकिन मार्शल लॉ के चलते वे अब भी पद पर बने हुए हैं। रूस पहले भी उनकी वैधता पर सवाल उठा चुका है। रूस ने स्पष्ट किया कि उसे यूक्रेन के यूरोपीय संघ में शामिल होने पर कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन यूक्रेन के नाटो सदस्य बनने का रूस पुरजोर विरोध करता रहेगा।

पेसकोव ने कहा, EU में शामिल होना किसी भी देश का संप्रभु अधिकार है, लेकिन जब बात सुरक्षा और सैन्य गठबंधन की आती है, तो रूस का रुख अलग रहेगा। इससे पहले, मंगलवार को सऊदी अरब के रियाद स्थित दिरियाह पैलेस में अमेरिका और रूस के शीर्ष अधिकारियों की गुप्त बैठक हुई। इस बैठक में रूस-यूक्रेन युद्ध समाप्त करने और अमेरिका-रूस संबंधों को बेहतर बनाने पर चर्चा हुई। यह बैठक ट्रंप प्रशासन की रूस नीति में बदलाव की ओर इशारा करती है। हालांकि, इस बैठक में यूक्रेनी अधिकारी शामिल नहीं हुए । इस पर यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा कि अगर यूक्रेन किसी बातचीत में शामिल नहीं होता, तो उसका कोई भी नतीजा हमें स्वीकार नहीं होगा।

स्वामी, प्रकाशक एवं मुद्रक श्रीमती ज्योती मिश्रा द्वारा कॉम्पेक प्रिंटर्स प्रा. लि. फ्री प्रेस हाउस 3/54, प्रेस कॉम्पलेक्स, ए.बी. रोड, इंदौर से मुद्रित एवं 45ए गुप्ता चैम्बर पहली मंजिल जावरा कंपाउंड इंदौर, (म.प्र.) से प्रकाशित।
प्रधान सम्पादक : अशीष मिश्रा आर.एन.आई. पंजीयन क्रमांक : एमपी/एच/आइएन 2009/34385 फोन नं : 0731-4202569 फैक्स नं : 0731-4202569